

03 "आप" ने की एलजी निवास पर जमकर की नारेबाजी

06 डॉक्टरों और इंजीनियरों से परे शुद्ध विज्ञान में करियर तलाशना

08 सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया

दिल्ली मेट्रो का चौथा फेज जल्द होगा शुरू जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच चलेगी मेट्रो

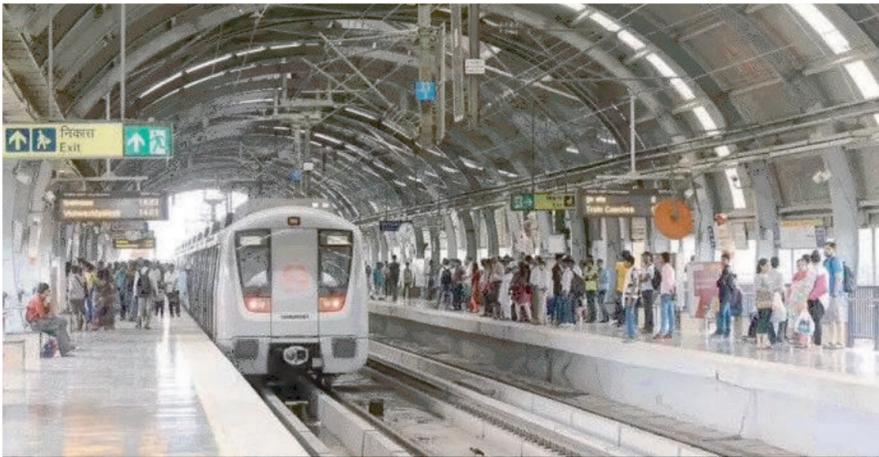
फेज चार के कॉरिडोर पर जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच जल्द मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। यह कॉरिडोर फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान समय में मजेंटा लाइन का हिस्सा है। इसके हो जाने से कृष्णा पार्क के आसपास की कालोनियों के अलावा विकासपुरी के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

संज्ञ बाटला

नई दिल्ली। फेज चार के जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर के ढाई किलोमीटर हिस्से पर जल्दी मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को सिर्फ अब मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से स्वीकृति मिलने का इंतजार है।

जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा
सीएमआरएस से हरी झंडी मिलते ही जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो चलने लगेगी। यह कॉरिडोर फेज चार में निर्माणाधीन करीब 2.9 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा है।

कृष्णा पार्क एक्सटेंशन नया स्टेशन बना
जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क के बीच ढाई किलोमीटर का भूमिगत कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर पर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन नया स्टेशन बनाया गया है। मंगलवार को सीएमआरएस (CMRS) ने इस कॉरिडोर व कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के सुरक्षा



मानकों का निरीक्षण किया। उम्मीद है कि परिचालन के लिए डीएमआरसी को जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी।

जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान मजेंटा लाइन का हिस्सा है। इसलिए जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने से मजेंटा लाइन पर नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से सीधे

कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। इससे कृष्णा पार्क के आसपास की कालोनियों के अलावा विकासपुरी के लोगों को भी फायदा होगा।

ठेकेदार की मनमानी, एमसीडी बेबस, वाहन चालकों को नहीं मिलती पर्ची; खो जाने पर नहीं कोई जवाबदेही

गीता कॉलोनी दस ब्लॉक में दिल्ली नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार की जमकर मनमानी चल रही है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी के आगे निगम बेबस है। वह सड़क पर भी अवैध पार्किंग चला रहा है और वाहन खड़ा करने वालों को पर्ची भी नहीं मिलती है। अगर चोरी हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है।



नई दिल्ली। गीता कॉलोनी दस ब्लॉक में दिल्ली नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार की जमकर मनमानी चल रही है। पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले लोगों को पार्किंग की पर्ची ही नहीं दी जा रही है। निगम ने पार्किंग के लिए जितना हिस्सा तय किया हुआ है, उससे अधिक हिस्से में अवैध पार्किंग करवाई जा रही है।

इतना ही नहीं इस पार्किंग में वाहन खड़ा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। उन्हीं वाहनों को खड़ा करवाया जाता है जिनके मालिक एक माह का शुल्क देते हैं। इस तरह निगम का कोई ध्यान ही नहीं है।

ठेकेदार के आगे निगम बेबस
गीता कॉलोनी दस ब्लॉक में निगम की अधिकृत पार्किंग चल रही है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी के आगे निगम बेबस है। निगम से सांठगांठ करके पार्किंग का ठेकेदार सड़क पर भी अवैध रूप से भी पार्किंग चला रहा है। पर्ची किसी को नहीं दी जाती है। अगर कोई वाहन चोरी हो गया तो ठेकेदार यह कहकर बच जाएगा कि पार्किंग की पर्ची दिखाओ। निगम आयुक्त को मामले को गंभीरता से देखना चाहिए।

पेट्रोल खत्म होने पर बुधस्पातवार रात को मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी थी, पर्ची मांगने पर भी ठेकेदार ने नहीं दी। डर लगा रहा था अगर मोटरसाइकिल

चोरी हो गई तो ठेकेदार तो अपनी बात से मुकर जाएगा। - सौरभ, निवासी गांधी नगर।

पार्किंग में पर्ची किसी को नहीं दी जाती है। शुरुआत से ही यहां पार्किंग ऐसे ही चल रही है, सबको पता है। जिसको जो करना है वह कर सकता है। किसी को पर्ची चाहिए तो वह दूसरी पार्किंग में वाहन खड़ा कर सकता है। जो एक माह का शुल्क देता है उसके वाहनों को ही खड़ा करवाया जाता है। - पार्किंग संचालक।

सारा मामला निगम के इंस्पेक्टर को बताया था। जिसके बाद अधिकारी ने ठेकेदार से बात की है और हर वाहन चालक को पर्ची देने के लिए कहा है। अगर ठेकेदार ऐसा नहीं करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। -संदीप कपूर, स्थानीय पार्किंग

फेम-3 योजना पूरी होने के करीब, समयसीमा की घोषणा करना अभी बाकी, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। फेम योजना के तीसरे चरण की अंतिम तैयारी चल रही है, लेकिन अभी इसकी समय सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हाल ही में एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि फेम III के कार्यान्वयन की तैयारी चल रही है और मंत्रालयों ने कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, इस बारे में सफाई की है।

भारत में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 2015 में फेम योजना तैयार की थी।

योजना का पहला चरण मार्च 2019 तक उपलब्ध था, जिसका बजट परिव्यय 895 करोड़ रुपये था। फेम इंडिया योजना के इस चरण में चार फोकस क्षेत्र थे - तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स।

इस योजना के पहले चरण में लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड वाहनों को लगभग 359 करोड़ रुपये की कुल मांग प्रोत्साहन के साथ समर्थन दिया गया था। इसके अलावा, योजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन के साथ तैनात किया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने चरण-1 के तहत लगभग 43 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशन/इन्फ्रास्ट्रक्चर

को भी मंजूरी दी थी।

प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जैसे कि परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना, इलेक्ट्रिक परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में एडवॉन्स रिसर्च के लिए एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना। इसके लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, नॉन-फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों को प्रोजेक्ट दी गई।

चरण 1 के दौरान हासिल नतीजों और अनुभव के आधार पर और उद्योग और उद्योग संघों सहित सभी हिस्सेदारों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, सरकार ने अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कुल बजटीय सहायता 11,500 करोड़ रुपये के साथ चरण-II को अधिसूचित किया। इस चरण-II में मुख्य रूप से सार्वजनिक और सड़क परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और मांग प्रोत्साहन के जरिए 7,262 ई-बस, 1,55,536 ई-3 व्हीलर, 30,461 ई-4 व्हीलर यात्री कार और 15,50,225 ई-2 व्हीलर का समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी योजना के तहत समर्थित है।

पर्यावरण पाठशाला: मेंढक, केंचुए और अन्य पारिस्थिति की तंत्र के साथी जो समाज के लिए अच्छे हैं : अंकुर

पर्यावरण का महत्व और उसके विभिन्न घटकों का योगदान हमें हमारी जीवनशैली में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पर्यावरण पाठशाला के अंतर्गत हम उन घटकों की चर्चा करेंगे जो हमारे समाज और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रमुख हैं मेंढक, केंचुए और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के साथी।



मेंढक
मेंढक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये छोटे जीव पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। मेंढक जल और भूमि दोनों में रहते हैं, जिससे वे प्रदूषण और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। मेंढक के लार्वा मच्छरों के लार्वा को खाते हैं, जिससे मच्छरों की जनसंख्या नियंत्रित रहती है। इसके अलावा, मेंढक छोटे कीटों और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं, जिससे कीटों की संख्या नियंत्रण में रहती है और खेती में होने वाले नुकसान कम होते हैं। मेंढक विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रसार को रोकने में भी मदद करते हैं।

केंचुए
केंचुए भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव मिट्टी को खोदकर और उसके अंदर के जैविक पदार्थों को मिलाकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिलती है। केंचुए जैविक पदार्थों को तोड़कर ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। केंचुओं की यह गतिविधि जैविक खेती और बागवानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के साथी
इसके अलावा, अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के साथी जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, चूहे, पक्षी

आदि भी हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मधुमक्खियां परागण में मदद करती हैं, जिससे फूलों और फलों का उत्पादन बढ़ता है। तितलियां भी परागण में मदद करती हैं और जैव विविधता को बनाए रखती हैं। चूहे और अन्य छोटे स्तनपायी भी जैविक तंत्र में मदद करते हैं, जिससे नए पौधों का जन्म होता है।

मेंढक, केंचुए और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के साथी हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन जीवों के बिना हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में नहीं रह सकता। हम इन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि

ये जीव हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इनका संरक्षण हमारे ही हित में है। पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से हम इन जीवों के महत्व को समझ सकते हैं और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं।

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन पारिस्थितिकी तंत्र के साथियों का संरक्षण करें और उनकी संख्या को बनाए रखें। इस प्रकार हम एक संतुलित और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

indiangreenbuddy@gmail.com

संस्कारशाला: जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अनुशासन और कृतज्ञता

प्रियंका श्रीवास्तव

संस्कार और कृतज्ञता मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। अनुशासन वह गुण है जो हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान बनाता है। यह हमें अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम अपनी और समाज की प्रगति में योगदान कर सकते हैं। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुगम और संगठित बनाते हैं, बल्कि वे समाज में भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

कृतज्ञता वह भावना है जो हमें दूसरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें हमारे जीवन में मिलने वाली सभी छोटी-बड़ी सहायता और सहयोग के प्रति सचेत और आभारी बनाती है। कृतज्ञता से भरे हुए लोग न केवल अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि वे समाज में भी एक स्वस्थ और सहायक वातावरण का निर्माण करते हैं।

जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अनुशासन और कृतज्ञता दोनों आवश्यक हैं। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने कार्यों को समय पर और सही ढंग से पूरा कर पाते हैं। इससे न केवल हमें व्यक्तिगत संतोष मिलता है, बल्कि समाज में भी हमारी विश्वसनीयता और सम्मान बढ़ता है। दूसरी ओर, जब हम कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति विनम्र और सहयोगी बनते हैं, जिससे समाज में आपसी समझ और सहयोग की भावना बढ़ती है।

अनुशासन और कृतज्ञता के माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को इन मूल्यों का महत्व समझाते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम एक जिम्मेदार और संगठित समाज की नींव रखते हैं। यह हमारे समाज को अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने में मदद करता है।



इस प्रकार, अनुशासन और कृतज्ञता न केवल व्यक्तिगत सफलता की कुंजी हैं, बल्कि वे समाज में भी शांति, सहयोग और समृद्धि का आधार बनते हैं। जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए इन मूल्यों का पालन अनिवार्य है, और यही हमारे समाज को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने में सहायक होगा।

बच्चों के लिए दैनिक जीवन में कृतज्ञता प्रदर्शित करने के महत्वपूर्ण टिप्स

कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मिलने वाली हर छोटी-बड़ी चीज की सराहना करना सिखाता है। बच्चों को यह गुण सिखाना उन्हें जिम्मेदार और विनम्र नागरिक बनाने में मदद करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं जिनसे बच्चे अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता प्रदर्शित कर सकते हैं:

धन्यवाद कहना सिखाएं: बच्चों को हर छोटी-बड़ी मदद के लिए 'धन्यवाद' कहना सिखाएं। चाहे कोई उन्हें खिलौना दे या उनकी मदद करे, उन्हें यह आदत डालें कि वे हमेशा आभार व्यक्त करें।

सराहना करें: चाहे वह उनके खिलौने हों, किताबें हों, या परिवार और दोस्त। इससे वे समझेंगे कि उन्हें जो मिला है वह महत्वपूर्ण है।

परिवार के समय को महत्व दें: बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने परिवार के साथ बिताए समय की कदर करें। यह उन्हें अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति कृतज्ञ होने का महत्व समझाएगा।

दूसरों की मदद करें: बच्चों को सिखाएं कि वे जब भी मौका मिले, दूसरों की मदद करें। इससे वे समझेंगे कि कृतज्ञता केवल लेना ही नहीं, बल्कि देना भी है।

शिक्षकों और दोस्तों का सम्मान करें: बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने शिक्षकों और दोस्तों के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। यह उन्हें उनके संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

प्रकृति का सम्मान करें: बच्चों को यह सिखाएं कि वे प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हों। उन्हें पेड़-पौधों की देखभाल करने, जानवरों का सम्मान करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की आदत डालें।

अपने पास की चीजों की सराहना करें: बच्चों को सिखाएं कि वे अपने पास मौजूद चीजों की

सिखाएं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ रहें। उन्हें नियमित व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने और स्वच्छता बनाए रखने की आदत डालें।

दैनिक आभार डायरी लिखें: बच्चों को एक आभार डायरी रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें वे रोजाना तीन चीजें लिखें जिनके लिए वे कृतज्ञ हैं। यह उन्हें सकारात्मक सोचने और छोटी-छोटी खुशियों की सराहना करने में मदद करेगा।

अनुभवों की सराहना करें: बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने अनुभवों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, की सराहना करें। इससे वे जीवन की हर स्थिति से कुछ नया सीख पाएंगे।

माफी मांगना और माफ करना सिखाएं: बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें और दूसरों को माफ करें। यह उनके मन में कृतज्ञता और सहानुभूति की भावना को बढ़ाएगा।

इन टिप्स के माध्यम से, बच्चे अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को शामिल कर सकेंगे और एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण के साथ बड़े हो सकेंगे।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063

कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

रेलवे में करीब 63 हजार सेवा कर्मियों में मात्र 9.36 फीसद यानी 5900 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं

सुषमा रानी

नई दिल्ली, भारतीय रेलवे में महिला सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी है। महिला सुरक्षा कर्मियों की यह कमी ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा रेल मंत्रालय से कई सवाल पूछे गए थे, जिनका मंत्रालय ने जवाब दे दिया है। मंत्रालय से मिले जवाब के मुताबिक ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में रोजाना सफर कर रही 66 लाख महिलाओं की सुरक्षा में 'मेरी सहेली' स्कीम के तहत मात्र 700 महिला सुरक्षा कर्मी ही तैनात हैं। जबकि रेलवे में करीब 63 हजार सेवा कर्मी तैनात हैं और इसमें मात्र 9.36 फीसद यानी 5900 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।

सांसद के मॉनसून सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा भारतीय रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में पूछे गए अंतरांगिक प्रश्न का जवाब रेल मंत्रालय द्वारा 25 जुलाई 2024 को दिया गया। केंद्र सरकार के जवाब में यह तथ्य सामने आया है कि भारतीय रेल में प्रतिदिन लगभग 66 लाख महिलाएं



आरक्षित डिब्बों में यात्रा करती हैं। जिनकी सुरक्षा के लिए मात्र 700 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। सरकार ने अपने जवाब में बताया कि स्कीम 'मेरी सहेली' के तहत 66 लाख महिला यात्रियों के लिए मात्र 700 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए जो अपने आम में बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है।

रेलवे सुरक्षा बल में रिक्तियों के संबंध में रआप सांसद के सवाल पर सरकार ने बताया कि वर्तमान में लगभग 4660 पद रिक्त हैं। सुरक्षा में महिला सुरक्षा कर्मियों

की भागीदारी के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने बताया कि 63 हजार के लगभग सेवा कर्मियों में मात्र 9.36 फीसद महिला सुरक्षा कर्मी हैं। यानी महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या मात्र 5900 है, जबकि रेलवे 66 लाख से अधिक महिला प्रतिदिन यात्रा करती है। महिला आरपीएफ कर्मियों की भारी कमी के कारण भारतीय रेल में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठता है। यह कमी महिला यात्रियों को कई तरह के जोखिमों में डाल सकती है।

शीला दीक्षित सरकार द्वारा बना इन्फ्रास्ट्रक्चर को केजरीवाल सरकार ने ध्वस्त कर दिया: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि मानसून की बारिश होने पर ऐसा कोई दिन नहीं जब किसी न किसी हादसे में लोगों की जान नहीं गई है, बीते कल भी जहांगीरपुरी में दो महिला इमारत ढहने से महिला सहित तीन लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि हादसे में गई मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में हुए हादसे के दिल्ली नगर निगम प्रशासन का यह कहना कि क्षेत्र को डीडीए ने विकसित किया था और अभी तक निगम को नालों और सड़कों को मरम्मत काम नहीं सौंपा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और राजधानी में में रोज गिरती इमारतों, करंट लगने और नालों में डूबकर मर रहे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दे।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में लगातार हो रहे हादसों की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, हर दिन लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र नगर



बेसमेंट कोचिंग हादसे पर दिल्ली कांग्रेस ने मांग की थी कि जांच सीबीआई के हाथों कराई जाए, हम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निगम आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और आदेश का स्वागत करते हैं। यादव ने कहा कि क्या सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये और अपनी जिम्मेदारी से भागने की स्थिति में रोज हो रही सभी मौतों पर उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा या सरकारें भी इन मामलों के प्रति अपनी जवाबदेही तय करेंगी।

उन्होंने कहा कि राजेन्द्र नगर कोचिंग हादसे में जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि

किसी ने किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जल भराव, करंट, इमारत गिरने से दबने, नाले खुले होने पर उनमें डूब कर लोग मर रहे तो दिल्ली की सरकारों और एजेंसियों को जिम्मेदारी के लेने मामले में पिछले एक महीने से भी अधिक समय से भाजपा और आम आदमी पार्टी लोगों की मौत पर राजनीति कर रही है, जो बहुत ही चिंताजनक है। मयूर विहार फेस 3 के खुले नाले में मां बेटे की गिरने मौत पर आम आदमी पार्टी का राज निवास पर प्रदर्शन करना और दिल्ली में अन्य

हादसों पर भाजपा का दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना करना कोरी राजनीति है। सरकारों को अपना दायित्व समझकर हादसे न हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्षों में राजधानी को विकसित बनाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था खड़ा किया था मौजूदा सरकार उसकी देखभाल और रख-रखाव नहीं कर पाई और पिछले 10 वर्षों में मौजूदा सरकार ने राजधानी के रोड़, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्डिंग, नाले सहित पूरे के पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया है। विश्वस्तरीय दिल्ली का विकास सब कुछ सरकारों की निष्क्रियता, अक्षमता और बदले की राजनीति के चलते सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकारों की निष्क्रियता, बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों के राजनीतिक दबाव में काम करने की स्थिति, और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को दिल्ली के विगड़ते हालात में दुर्लभ जिम्मेदारी की जरूरत है।

धर्म निरपेक्ष नालंदा विश्वविद्यालय में पूर्ववत जैन दर्शन और प्राकृत भाषा पाठ्यक्रम आरंभ करने की विश्व जैन संगठन की मांग

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन ने कहा कि 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर विश्वविद्यालय में जैन दर्शन और प्राचीन प्राकृत भाषा पाठ्यक्रम शामिल न किए जाने, नालंदा और राजगीर में जैन धर्म के प्रचलन में होने, भगवान महावीर द्वारा चतुर्मास किए जाने और यहां से खुदाई में प्राप्त प्राचीन जैन मंदिर और प्रतिमाओं का उल्लेख न करने का कारण समझ नहीं आया।

श्री संजय जैन ने बताया कि लोक सभा में 26 अगस्त 2020 को नालंदा विश्वविद्यालय बिल - 2010 पर चर्चा में चितौड़गढ़ सांसद डॉ गिरिजा व्यास द्वारा बिहार में 2500 वर्ष पूर्व गुणशिला यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए जैन दर्शन की शिक्षा और कुंडलपुर में शारीरिक प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी देते हुए जैन नामोकार महामंत्र उल्लेख करते हुए यूनिवर्सिटी में धर्म निरपेक्षता के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा के साथ-साथ जैन दर्शन सिद्धांत पढ़ाने की अनुशंसा की थी और सांसद श्री बाल आटे व अन्य सांसदों ने भी अनुमोदन की थी लेकिन वर्तमान में यूनिवर्सिटी में मात्र वैदिक और बौद्ध धर्म शिक्षा दिए जाना जैन दर्शन और प्राकृत के साथ



भेदभाव है।

संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में नालंदा का जैन ग्रंथों व भगवान महावीर द्वारा नालंदा में 14 चतुर्मास काल व्यतीत करने का उल्लेख करने और प्राचीन विश्वविद्यालय के समय 4-5 वी सदी के प्राचीन जैन मंदिर व इसमें 15वी सदी की भगवान महावीर की प्रतिमा की खोज की थी और नालंदा विहार क्रमांक 1 से ऋषभदेव भगवान की 9-10 वी सदी की प्राचीन प्रतिमा और नालंदा विहार 9, 10, 11 से जैन तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त होना यहां प्राचीन काल से जैन धर्म प्रचलन में होने के प्रमाण है।

श्री संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30 प्रमुख यूनिवर्सिटी में जैन विद्या और

भारत की प्राचीनतम प्राकृत भाषा के पाठ्यक्रम संचालित है।

पुरातत्व विभाग द्वारा भी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से यूनेस्को को नालंदा से जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं प्राप्त होने और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में जैन शास्त्र पढ़ाए जाने की लिखित जानकारी दी गई है। जवाहर लाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी 9 जुलाई 2024 को जैन दर्शन के लिए सेंटर आरंभ करने के प्रस्ताव पारित किया गया है।

श्री संजय जैन ने विश्व जैन संगठन और समस्त जैन समाज की ओर से केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में नालंदा का जैन ग्रंथों व भगवान महावीर द्वारा नालंदा में 14 चतुर्मास काल व्यतीत करने का उल्लेख करने और प्राचीन विश्वविद्यालय के समय 4-5 वी सदी के प्राचीन जैन मंदिर व इसमें 15वी सदी की भगवान महावीर की प्रतिमा की खोज की थी और नालंदा विहार क्रमांक 1 से ऋषभदेव भगवान की 9-10 वी सदी की प्राचीन प्रतिमा और नालंदा विहार 9, 10, 11 से जैन तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त होना यहां प्राचीन काल से जैन धर्म प्रचलन में होने के प्रमाण है।

श्री संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30 प्रमुख यूनिवर्सिटी में जैन विद्या और

'गौशाला' बने उत्तरी-बाहरी व पश्चिमी दिल्ली के सड़क मार्गों पर गरु माता सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा व यात्री सुविधा पुनर्स्थापित करने हेतु गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत ने किया निवेदन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के कृष्णा कुंज, बी-6/36, सैक्टर-15, रोहिणी स्थित एनजीओ गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत (पंजी०) ने 'गौशाला' बने उत्तरी-बाहरी व पश्चिमी दिल्ली के सड़क मार्गों पर गरु माता सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा व यात्री सुविधा पुनर्स्थापित करने हेतु महामहिम उपराज्यपाल महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त महोदय, दिल्ली पुलिस, प्रमुख अभियंता महोदय, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आयुक्त महोदय, दिल्ली नगर निगम से निवेदन किया है।

उन्होंने इस निवेदन में कहा कि महोदय, इस निवेदन के माध्यम से हम आपका ध्यान उत्तरी-बाहरी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में दस-पन्द्रह-बीस बीस गऊ माताओं के मुख्य बैठने, खाने-पीने व सड़क एवं सैण्ट्रल वर्ज पर रहने के कारण जनता व गऊ माताओं को ही रोज गंभीर असुविधाओं व सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

ये गऊ माता शुण्ड बनाकर मुख्य मार्गों पर विचरण कर रही हैं।

वहीं सड़क के बीचोंबीच व डिवाइडर के समीप बैठ जाती हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर जनता इनके लिए खानपान सामग्री छोड़ देते हैं।

अनेक बार गऊ माताएं शुण्ड बनाकर सड़क मार्ग पर यातायात प्रवाह ही बाधित कर देती हैं। वाहनों को इनके बीच से होकर दाएं-बाएं दाएं-बाएं मुड़कर आगे बढ़ना पड़ता है।

ऐसे में विशेषकर सायंकाल व रात्रिकाल में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में न केवल गऊ माताएं अपितु जनता भी चोटिल हो रही है।

पिछले लगभग एक-दो वर्ष समय से यह समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है।



पहले जहाँ एक-दो गऊ माता सड़क पर कभी-कभार ही मिलती थीं, अब इनके शुण्ड के शुण्ड चौबीसों घंटे सड़क मार्ग व सैण्ट्रल वर्ज पर पाए जा रहे हैं।

निम्नलिखित सड़क मार्गों पर यह समस्या किसी भी समय देखी जा सकती है:

(01) रिंग रोड स्थित ब्रिटानिया फ्लाईओवर से वजीरपुर फ्लाईओवर की ओर बढ़ते समय शमशान भूमि के समीप फुट ओवर ब्रिज के आसपास सड़क मार्ग।

(02) बाहरी रिंग रोड स्थित प्रशांत विहार एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे सड़क मार्ग व सैण्ट्रल वर्ज पर। यहाँ सैण्ट्रल वर्ज पर तो गऊशाला सी बने गई प्रतीत हो रही है।

40-50 गऊ माताएं व बछड़े।

(03) रोहिणी सैक्टर-15 व 16 विभाजक मार्ग पर राधे-राधे हलवाई से बंसल भवन के बीच सड़क मार्ग पर। 20-30 की संख्या में गऊ माताएं।

(04) रोहिणी सैक्टर-15, बी-4 रोड स्थित नाला सेतु के आसपास 20-30 गऊ माताएं। हैंस विहार अपार्टमेंट की दीवार के विपरीत।

(05) अन्य अनेक सड़क मार्ग। ये गऊ माताएं किसी न किसी डेयरी की हैं जोकि प्रातः सायं इनका दूग्ध दोहन कर इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। प्रत्येक गऊ माता की त्वचा पर किसी न किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित है।

समस्या को दर्शाती कुछ फोटो संलग्न कर रहे हैं कृपया। अग्रिम प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु):

उपायुक्त महोदय, रोहिणी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम
उपायुक्त महोदय, केशव पुरम क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम
उपायुक्त महोदय, यातायात, उत्तरी परिक्षेत्र, दिल्ली पुलिस
विनम्र निवेदन है कि संबंधित विभागों व अधिकारियों को इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेकर अविलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की सलाह जारी करें महोदय।

मैकावर बीके प्राइवेट लिमिटेड ने सफदरजंग अस्पताल को महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण दिए

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, रोटी क्लब ऑफ दिल्ली के माध्यम से मैकावर बीके प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में, सफदरजंग अस्पताल को महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण दिए हैं। तीन यूरेटरोस्कोप और 9 इन्व्यूजन पंपों से युक्त इस योगदान से अस्पताल की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की क्षमता बढ़ेगी।

इस अवसर पर एक हैडओवर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने वाले सभी संगठनों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। वीएएमएससी और सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अतिरिक्त एमएस, सीएसआर समिति टीम के सदस्य, एचओडी, संकाय और अस्पताल के कर्मचारी भी मौजूद थे।

रोटी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ईस्ट के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, रहमारा क्लब हमारे समुदाय में ठोस बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योगदान सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। हम मैकावर बीके प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अजय



गुप्ता ने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी कंपनी के समर्थन को दोहराया। गुप्ता ने कहा, रहम सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए साझेदारी की शक्ति में विश्वास करते हैं। रोटी क्लब के साथ यह सहयोग हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रभावी रूप से योगदान करने की अनुमति देता है। डॉ. वंदना तलवार ने इस पहल के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, रये अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण हमारी निदान और उपचार क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करेगी। हम रोटी क्लब और मैकावर बीके प्राइवेट लिमिटेड के सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके उदार योगदान के लिए आभारी हैं। इन्हें उपकरणों से रोगी देखभाल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। मूत्र पथ के मुद्दों के निदान और उपचार के लिए यूरेटरोस्कोप महत्वपूर्ण हैं, जबकि

इन्व्यूजन पंप विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में आवश्यक उपकरण हैं। यह योगदान रोटी क्लब के चल रहे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का समर्थन करना और व्यापक समुदाय के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना है। यह पहल भारत में स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवा संगठनों, निजी कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच सहयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।

चूंकि सफदरजंग अस्पताल आबादी के एक बड़े हिस्से की सेवा करना जारी रखता है, इसलिए यह उपकरण योगदान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मयूर विहार फेस तीन में एलजी के अधीन डीडीए के नाले में गिरकर हुई मां-बेटे की मौत से आक्रोशित आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एलजी सचिवालय पर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और एलजी से इस्तीफे की मांग की। "आप" प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन में कई विधायक, महिला, यूथ विंग व लीगल सेल के पदाधिकारी समेत बड़ी तादात में कार्यकर्ता शामिल हुए। एलजी साहब इस्तीफा दो, डीडीए के अफसरों को सस्पेंड करो समेत अन्य नारे लिखे तख्तियों के साथ आप कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करे। एलजी से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। "आप" का कहना है कि एलजी के अधीन डीडीए की लापरवाही से मां-बेटे की मौत हुई है। एलजी साहब केन्द्र की भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। इसलिए अभी तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और न तो पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा ही हुई है।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे

बड़ी तादात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी सचिवालय पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शन में शामिल पार्टी के नेता, विधायक, पाषंद व कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठकर एलजी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। डीडीए की लापरवाही से हुई मां-बेटे की दुखद मौत से नाराज "आप" कार्यकर्ताओं और महिला विंग ने दिल्ली के नाले साफ करो, एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी समेत अन्य नारे लगाते हुए एलजी को तत्काल इस्तीफा देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस प्रचंड विरोध प्रदर्शन में "आप" के विधायक हाजी यूनुस, अब्दुल रहमान, राजेन्द्र पाल गौतम और अखिलेश पति त्रिपाठी समेत अन्य विधायक शामिल हुए। इनके अलावा पार्टी की परिषद नेता रीना गुप्ता, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी, यूथ विंग के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य विंग के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान "आप" प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि हम एलजी साहब के अधीन डीडीए के



अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मयूर विहार फेज 3 में मां-बेटे की मौत हुई है। एलजी साहब उन्हें इंसाफ दें और इस मामले से बचने की न तो कोशिश करें और न ही झूठ बोलें। भाजपा के लोग हर जगह प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार वो भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डीडीए का नाला है। डीडीए सीधे-सीधे एलजी के अधीन आता है। लेकिन एलजी साहब अब इससे नहीं बच सकते। उन्हें कार्रवाई करते हुए अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। उस मां-बेटे की क्या गलती

थी? अगर वो नाले के पास से गुजर रहे थे और नाला नहीं ढका था, तो ये अधिकारियों की लापरवाही थी। एलजी साहब उन्हें क्यों बचा रहे हैं? वहीं, "आप" नेता रीना गुप्ता ने कहा कि एलजी दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। वो अफसरों को कंट्रोल करके दिल्ली के सारे काम रूकवा रहे हैं। आज हम उनसे उनके इस्तीफे की मांग करने आए हैं। अगर एलजी वी के सक्सेना को मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो वो अपना इस्तीफा देकर मैदान में आए और

मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ें। वो जानबूझकर दिल्ली सरकार के काम रोक रहे हैं। डीडीए सीधे-सीधे एलजी साहब के अधीन है। उसके खुले नाले में गिरने से एक मां-बच्चे की मौत हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस डीडीए की जिम्मेदारी एलजी साहब की है, वो उसका काम देखने के बजाय सरकार के सारे विभागों में दखलअंदाजी करते हैं या किसी मंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। अगर उनसे डीडीए नहीं संभल पा रहा है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दें।

गौतमबुद्ध नगर के चार परिषदीय स्कूलों पर लटक सकता है ताला, छात्र से अधिक है शिक्षकों की संख्या

परिवहन विशेष न्यूज़

गौतमबुद्ध नगर में परिषदीय स्कूलों को संवारा जा रहा है। भले ही स्कूलों का कार्यालय हो रहा हो लेकिन यहां पर लगातार छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। हाल ही में शासन की ओर से जनपद के 152 स्कूलों की सूची जारी की गई थी जिनमें 50 से कम छात्रों का नामांकन था। उनमें दनकौर जेवर और दादरी के ही 132 स्कूल शामिल थे।

ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले गौतमबुद्ध नगर के चार परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या कम होने के कारण ताला लटक सकता है। यदि ऐसा होता है तो इनमें पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे उन्हें दिक्कत होगी। शिक्षक अन्य स्कूल में समायोजित होंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से परिषदीय स्कूलों को संवारा जा रहा है। भले ही स्कूलों का कार्यालय हो रहा हो, लेकिन स्कूलों से लगातार छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। हाल ही में शासन की ओर से जनपद के 152 स्कूलों की सूची जारी की गई थी, जिनमें 50 से कम छात्रों का नामांकन था। उनमें दनकौर, जेवर और दादरी के ही 132 स्कूल शामिल थे। दादरी ब्लॉक के प्राथमिक रोशनगढ़ी और प्राथमिक स्कूल नई बीर में कई कक्षाओं में एक भी छात्र का नामांकन नहीं है।

दोनों स्कूलों में दो-दो छात्रों का ही नामांकन है। दनकौर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बूढ़ा घरवरा और प्राथमिक स्कूल मिल्क खरेली भाव में भी छात्रों की संख्या 10 से कम है। चारों स्कूलों में



शिक्षकों की संख्या तीन-तीन से अधिक है। नई शिक्षा नीति के तहत एक शिक्षक 30 छात्रों को पढ़ाएगा, लेकिन यहां छात्रों से अधिक शिक्षक तैनात हैं।

नामांकन बढ़ाने की नहीं बनी योजना
पिछले कई महीनों से स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है। उसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से होने कोई रणनीति नहीं बनाई गई।

पिछले सत्र में शिक्षकों ने घर-घर जाकर अभिभावकों को परिषदीय स्कूलों में मिल रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। आउट आफ स्कूल छात्रों की गांव-गांव जाकर पहचान करनी थी। उस अभियान को भी गति नहीं मिल पाई।

आबादी नहीं होने का शिक्षक बता रहे कारण

छात्रों की संख्या कम होने का कारण शिक्षक आबादी नहीं होना बता रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि मजरा में दो तीन परिवार ही रहते हैं। जो संपन्न परिवार हैं। वह अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं। वहीं नई बिल स्कूल इंस्ट्रुमेंट परिफेरल के पास में है। जहां आए दिन हादसे होते हैं। हादसों के डर के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं।

आज से शुरू होगा हॉस्पिटैलिटी एक्सपो, 20 हजार से अधिक खरीददारों के पहुंचने का अनुमान



इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो नोएडा में आज से इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो (IHE 2024) का सातवां संस्करण शुरू हो रहा है। जो 3 अगस्त से 6 अगस्त 2024 तक भारत एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में आयोजित होगा। माना जा रहा है कि इसमें 20 हजार से अधिक खरीददारों के आने की संभावना है। इसमें वियतनाम से राजनयिक हॉस्पिटैलिटी पेशेवर शोफ भी हिस्सा लेंगे।

गुरुग्राम। ग्रेटर नोएडा। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के सातवें संस्करण का आयोजन तीन से छह अगस्त तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा। इसमें एक हजार से अधिक प्रदर्शकों और 20 हजार से अधिक खरीददारों के पहुंचने का अनुमान है।

एक्सपो में नई प्रौद्योगिकी की दी जाएगी जानकारी
जो लक्जरी होटल, रिसार्ट्स, होमस्टे, रेस्तरां, क्लाउड किचन से जुड़े हैं। इंडिया इंटरनेशनल

हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के अतिरिक्त कैटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया और आयुर्वेद एक्सपो का भी आयोजन होगा। इस एक्सपो में नवीनतम रुझानों के साथ नई प्रौद्योगिकी, सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

वियतनाम से राजनयिक, हॉस्पिटैलिटी पेशेवर भी होंगे शामिल
इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो के लिए वियतनाम को साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। वियतनाम से राजनयिक, हॉस्पिटैलिटी पेशेवर, शोफ एक्सपो में शामिल होंगे। इसका मकसद भारत और वियतनाम के बीच हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के साथ व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।

इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन डा. राकेश कुमार ने कहा है कि इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो नई साझेदारियां बनाने और विकास एवं सहयोग बढ़ाने का मौका है, ताकि हॉस्पिटैलिटी उद्योग वैश्विक मंच पर फलताफूलता रहे।

कांठड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर किया हमला, गाड़ियां तोड़ी; इलाके में तनाव का माहौल

पुलिस के अनुसार सेक्टर-12 प्रेम नगर के दो गुट 27 जुलाई को कांठड़ लेकर हरिद्वार के लिए गए थे। इसमें एक झुग्गी का गुट है और एक सेक्टर 12 में रहने वाले लोगों का। सेक्टर 12 निवासी दीपक ने बताया कि 27 जुलाई को दोनों गुट कांठड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने लगे तो झुग्गी वाले गुट ने उनके गुट से तेज संगीत का कांटीशन करने की बात कही।

गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 प्रेम नगर स्थित मंदिर में जलाभिषेक के बाद कांठड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। यह हमला लाठी डंडों, रॉड और तलवारों से किया गया। हमले में दूसरे गुट के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तोड़फोड़ और पथराव में आधा दर्जन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। टकराव की सूचना के बाद भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।

पुलिस के अनुसार सेक्टर-12 प्रेम नगर के दो गुट 27 जुलाई को कांठड़ लेकर हरिद्वार के लिए गए थे। इसमें एक झुग्गी का गुट है और एक सेक्टर 12 में रहने वाले लोगों का। सेक्टर 12 निवासी दीपक ने बताया कि 27 जुलाई को दोनों गुट कांठड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने लगे तो झुग्गी वाले गुट ने उनके गुट से तेज संगीत का कांटीशन करने की बात कही। जब दीपक के गुट ने इसके लिए मना किया तो उन्होंने झगड़ा किया। उस

समय विवाद सुलझ गया। आरोप है कि झुग्गी वाले गुट के लोगों ने धमकी दी थी कि कांठड़ लाने के बाद वह उन्हें सबक सिखाएंगे।

सेक्टर 12 के मकान में घुसकर की मारपीट

शुक्रवार सुबह दोनों गुट वापस आए और प्रेम नगर चौक स्थित मंदिर में जलाभिषेक किया। सेक्टर 12 निवासी गुट के लोग अपने-अपने घरों में थे। इसी दौरान झुग्गीयों में रहने वाले कांठड़ियों के गुट के 15 से ज्यादा लोग हाथ में लाठी-डंडे और तलवार लेकर सेक्टर 12 में बने एक मकान में घुस गए और दूसरे गुट के लोगों से मारपीट की। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। लोगों से मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हो गई। इसके बाद आरोपितों ने बाहर खड़ी स्कॉर्पियो और टाटा 407 गाड़ी को भी पत्थरों व लाठी-डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया।

महिलाओं ने किया प्रदर्शन, रोड जाम करने की कोशिश

टकराव की सूचना के बाद सेक्टर 14 समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नागरिक अस्पताल भेजा गया। वहीं पीड़ितों से पूछताछ के बाद जब आरोपितों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो झुग्गी की महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां की महिलाएं सेक्टर 12 चौक पर आ गईं और जाम लगाया की कोशिश की। पुलिस बल ज्यादा होने से महिलाओं को वहां से हटा दिया गया।

नोएडा मेट्रो में अब मुसाफिरों का सफर होगा आसान, एक्वा लाइन पर लगेगा एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी डॉ. लोकेश एम ने बताया कि एक्वा लाइन के सभी स्टेशनों की अलग-अलग लोकेशन पर इनको लगाया जाएगा ताकि मुसाफिर आसानी से इनको देख सकें और मेट्रो की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए 21 मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स में कुल 42 पीआईडीएस इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा आने जाने दोनों प्लेटफॉर्म पर 2-2 सिस्टम लगाए जाएंगे।

नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मुसाफिरों का सफर आसान बनाने के लिए एक्वा लाइन पर एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (पीआईडीएस) लगाया गया। यह सिस्टम लाइन के सभी 21 मेट्रो स्टेशन पर संचालित किया जाएगा।

इसके लिए एनएमआरसी प्रबंधन ने रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (पीआईडीएस) जारी किया है। लो कॉस्ट कंपनी का चयन किया जाएगा। परियोजना में

11.27 करोड़ रुपये खर्च कर कुल 88 पीआईडीएस सिस्टम स्टेशनों पर इंस्टॉल होंगे। कार्य में 10 माह का समय लगेगा।

कॉन्कोर्स में कुल 42 पीआईडीएस इंस्टॉल

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एमडी डॉ. लोकेश एम ने बताया कि सभी स्टेशनों की अलग-अलग लोकेशन पर इनको लगाया जाएगा, ताकि मुसाफिर आसानी से इनको देख सकें और मेट्रो की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए 21 मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स में कुल 42 पीआईडीएस इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा आने जाने दोनों प्लेटफॉर्म पर 2-2 सिस्टम लगाए जाएंगे। जिस कंपनी को काम सौंपा जाएगा, जो सफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन, टैरिंटिंग व कमीशनिंग का काम करेगी।

टेंडर शर्त अनुसार उसे 24 माह तक सभी डिवाइस का रखरखाव का काम भी करना होगा। सभी पीआईडीएस डिस्प्ले बोर्ड टूट कर एलईडी बेस्ड होंगे। इसके अलावा इनको कंट्रोल करने के लिए एक कामन वर्क स्टेशन भी विकसित किया

जाएगा। आधुनिक पीआईडीएस सिस्टम के इंस्टॉलेशन से इस रूट पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों तक जानकारीयों पहुंचने में एनएमआरसी को मदद मिलेगी।

इन स्टेशनों पर लगेगे पीआईडीएस सिस्टम

एक्वा लाइन के 21 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। यह स्टेशन नोएडा सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा में डिपो स्टेशन तक है। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के अप व डाउन प्लेटफॉर्म पर 2-2 यानि कुल 4 पीआईडीएस इंस्टॉल होंगे। सेक्टर-50, सेक्टर-76, सेक्टर-81, सेक्टर-101, एनएसईजेड, सेक्टर-83, सेक्टर-137, सेक्टर-142, सेक्टर-143, सेक्टर-144, सेक्टर-145, सेक्टर-146, सेक्टर-147, सेक्टर-148, केपी-2, परी चौक, अल्फा-1, डेल्टा-1 तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्टेशन के अप व डाउन प्लेटफॉर्म पर 2-2 यानि कुल 4



पीआईडीएस इंस्टॉल होंगे। डिपो स्टेशन पर अप व डाउन प्लेटफॉर्म पर 2-2 पीआईडीएस के अतिरिक्त तीसरे प्लेटफॉर्म पर भी 2 पीआईडीएस इंस्टॉल होंगे।

यह होगा फायदा
● सिस्टम की मदद से प्लेटफॉर्म आने वाली मेट्रो की जानकारी मिलेगी।
● कितने समय में प्लेटफॉर्म पर और

किस अंतराल पर आएगी मेट्रो जानकारी मिलेगी

● समय से लेकर मौसम की जानकारी अपडेट करेगा।
● किसी प्रकार की अनहोनी होने पर इसे सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ा जा सकेगा।
● अनाउंसमेंट संबंधित जानकारी भी इस पर फ्लैश की जा सकेगी।

सत्ता हो विपक्ष, राजनीति तो स्वाभाविक है

जहां तक बजट में राजनीति का सवाल है तो शायद ही कोई सरकार या दल होगा, जिसने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत बजट में राजनीति ना की होगी।

विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने बजट को लेकर राजनीति की है। विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्पमत सरकार को समर्थन देने की कौमल वसुली है। आरोप यह भी है कि सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, जबकि अन्य राज्यों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। आरोप को बढ़ाते हुए विपक्ष यहां तक कह रहा है कि यह पूरे देश का बजट नहीं है। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि मौजूदा बजट उसके चुनाव घोषणा पत्र की कॉपी है।

जहां तक बजट में राजनीति का सवाल है तो शायद ही कोई सरकार या दल होगा, जिसने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत बजट में राजनीति ना की होगी। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, उसका अपना एजेंडा होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है। बजट हो या अन्य सरकारी फैसले, हर राजनीतिक दल और सरकार अपने कदम उठाते वक्त उनका ध्यान रखती है। इसके साथ ही हर राजनीतिक दल अपने भावी और लक्षित वोट बैंक को लुभाने के लिहाज से भी फैसले लेता है। हर राजनीतिक दल की चाहत होती है कि उसका मौजूदा वोट आधार बढ़े। इस लिहाज से भी वह अपने राजनीतिक फैसले लेता है और उसकी सरकार भी अपनी नीतियां वही सिखावे से बनाती और बढ़ाती है। इस नजरिए से देखें तो अगर मोदी सरकार ने नीतीश और नायडू के राज्यों को कुछ विशेष सहुलियतें दी है तो कोई गलत नहीं है। अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह जनसंख्या पलायन का दंश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के

साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहुलियत देनी पड़ी तो दे। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। सिर्फ बिहार और आंध्र ही नहीं, जो राज्य पिछड़ा है, उसे आगे लाने और उसे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मदद की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अव्वल तो हम देश को एक इकाई के तौर पर देखने का दावा करते हैं। अपना संविधान नागरिक को देश की मूल इकाई घोषित करता है। इस लिहाज से हर नागरिक बराबर है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक नजरिए से देखें तो हर नागरिक बराबरी की बेंच पर नहीं बैठा है। समान मतदान और कानून के सामने बराबरी के अधिकार ने एक हद तक बराबरी की इस अवधारणा को जिंदा जरूर रखा है। यह बात और है कि अक्सर अमीर और गरीब के लिए कानूनी पेच और प्रक्रियाएं, यहां तक कि न्यायिक अवधारणा भी बदल जाती है। इन बातों को छोड़ दें तो कम से कम आर्थिक आधार पर बराबरी की ओर बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। प्रशासनिक सहुलियत और सांस्कृतिक आधार पर हमने राज्य गठित कर लिए तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी असमानताओं को अनदेखी की जाए। किसे नहीं पता है कि बिहार के उत्तरी हिस्से में हर साल कोसी नदी प्रलय लेकर आती है। जिससे तकरीबन आधार बिहार नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहता है। इसी तरह समूचे देश को पता है कि तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद आंध्र की राजधानी नहीं रहा। उसे राजधानी बनाने के लिए संसाधन चाहिए ही होंगे। इसलिए अगर बिहार और आंध्र को सहुलियतें कुछ ज्यादा मिली थीं तो उसे राजनीतिक चरम से देखने की बजाय जमीनी हकीकत के लिहाज से समझा जाना चाहिए।

वैसे यह भी अर्ध सत्य ही है कि बाकी राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। जबकि इस बजट में अगर रेल परियोजनाएं हैं, अगर कृषि बजट को सवा लाख करोड़ से बढ़ाकर एक करोड़ 52 लाख करोड़ कर दिया गया है, अगर सड़क

परियोजनाओं की बाढ़ लाई गई है, अगर केंद्रीय सहुलियत देनी पड़ी तो दे। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। सिर्फ बिहार और आंध्र ही नहीं, जो राज्य पिछड़ा है, उसे आगे लाने और उसे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मदद की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अव्वल तो हम देश को एक इकाई के तौर पर देखने का दावा करते हैं। अपना संविधान नागरिक को देश की मूल इकाई घोषित करता है। इस लिहाज से हर नागरिक बराबर है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक नजरिए से देखें तो हर नागरिक बराबरी की बेंच पर नहीं बैठा है। समान मतदान और कानून के सामने बराबरी के अधिकार ने एक हद तक बराबरी की इस अवधारणा को जिंदा जरूर रखा है। यह बात और है कि अक्सर अमीर और गरीब के लिए कानूनी पेच और प्रक्रियाएं, यहां तक कि न्यायिक अवधारणा भी बदल जाती है। इन बातों को छोड़ दें तो कम से कम आर्थिक आधार पर बराबरी की ओर बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। प्रशासनिक सहुलियत और सांस्कृतिक आधार पर हमने राज्य गठित कर लिए तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी असमानताओं को अनदेखी की जाए। किसे नहीं पता है कि बिहार के उत्तरी हिस्से में हर साल कोसी नदी प्रलय लेकर आती है। जिससे तकरीबन आधार बिहार नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहता है। इसी तरह समूचे देश को पता है कि तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद आंध्र की राजधानी नहीं रहा। उसे राजधानी बनाने के लिए संसाधन चाहिए ही होंगे। इसलिए अगर बिहार और आंध्र को सहुलियतें कुछ ज्यादा मिली थीं तो उसे राजनीतिक चरम से देखने की बजाय जमीनी हकीकत के लिहाज से समझा जाना चाहिए।

वैसे यह भी अर्ध सत्य ही है कि बाकी राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। जबकि इस बजट में अगर रेल परियोजनाएं हैं, अगर कृषि बजट को सवा लाख करोड़ से बढ़ाकर एक करोड़ 52 लाख करोड़ कर दिया गया है, अगर सड़क



इंटरनेशनल एक्सपो नोएडा में आज से इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो (IHE 2024) का सातवां संस्करण शुरू हो रहा है। जो 3 अगस्त से 6 अगस्त 2024 तक भारत एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में आयोजित होगा। माना जा रहा है कि इसमें 20 हजार से अधिक खरीददारों के आने की संभावना है। इसमें वियतनाम से राजनयिक हॉस्पिटैलिटी पेशेवर शोफ भी हिस्सा लेंगे।

इसके लिए एनएमआरसी प्रबंधन ने रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (पीआईडीएस) जारी किया है। लो कॉस्ट कंपनी का चयन किया जाएगा। परियोजना में

इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो नोएडा में आज से इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो (IHE 2024) का सातवां संस्करण शुरू हो रहा है। जो 3 अगस्त से 6 अगस्त 2024 तक भारत एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में आयोजित होगा। माना जा रहा है कि इसमें 20 हजार से अधिक खरीददारों के आने की संभावना है। इसमें वियतनाम से राजनयिक हॉस्पिटैलिटी पेशेवर शोफ भी हिस्सा लेंगे।

गुरुग्राम। ग्रेटर नोएडा। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के सातवें संस्करण का आयोजन तीन से छह अगस्त तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा। इसमें एक हजार से अधिक प्रदर्शकों और 20 हजार से अधिक खरीददारों के पहुंचने का अनुमान है।

इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो के अतिरिक्त कैटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया और आयुर्वेद एक्सपो का भी आयोजन होगा। इस एक्सपो में नवीनतम रुझानों के साथ नई प्रौद्योगिकी, सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

वियतनाम से राजनयिक, हॉस्पिटैलिटी पेशेवर भी होंगे शामिल

इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो के लिए वियतनाम को साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। वियतनाम से राजनयिक, हॉस्पिटैलिटी पेशेवर, शोफ एक्सपो में शामिल होंगे। इसका मकसद भारत और वियतनाम के बीच हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के साथ व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।

इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन डा. राकेश कुमार ने कहा है कि इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो नई साझेदारियां बनाने और विकास एवं सहयोग बढ़ाने का मौका है, ताकि हॉस्पिटैलिटी उद्योग वैश्विक मंच पर फलताफूलता रहे।

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



जापानी प्रतिद्वंद्वी निसान और होंडा आगे बढ़ने के लिए ईवी घटकों और एआई अनुसंधान को करेंगे साझा

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता निसान और होंडा ने कहा कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी जैसे घटकों को साझा करने और स्वायत्त ड्राइविंग के लिए संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर अनुसंधान करने की योजना बना रहे हैं। तीसरी जापानी निर्माता कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स कॉर्पोरेशन भी निसान-होंडा साझेदारी में शामिल हो गई है। उसका मानना है कि विद्युतीकरण पर केंद्रित

आउट उद्योग में नाटकीय बदलावों के अनुरूप गति और आकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निसान मोटर कंपनी और होंडा मोटर कंपनी के बीच प्रारंभिक समझौते की घोषणा मार्च में की गई थी। 1100 दिनों की बातचीत के बाद, कंपनियों के अधिकारियों ने इस बात की तय्यारी दिखाई। जापानी वाहन निर्माता हाल के दशकों में गैसोलिन इंजन के युग पर हावी रहे हैं, लेकिन वे अमेरिका की टेस्ला और चीन की

बीवाईडी जैसी ग्रीन कारों के क्षेत्र में नए खिलाड़ियों से पीछे रह गए हैं। होंडा के मुख्य कार्यकारी तोशीहिरो मिबे ने कहा, 'रजो कंपनियाँ बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पातीं, वे टिक नहीं पातीं।' एर और हम सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एर उन्होंने कहा कि निसान और होंडा एक ही बैटरी का उपयोग करेंगे और ईवी एक्सल के लिए मोटर और इनवर्टर के लिए

एक ही विनिर्देश अपनाएंगे।

माइबे और निसान के समकक्ष माकोतो उचिदा ने एक साथ मिलकर, जिसे बार-बार रमित्त बनाना कहा है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए, कंपनियों ने प्रौद्योगिकी में अधिक रणनीतिक निवेश की योजना बनाई है और मात्रा को बढ़ाकर लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा है।



ब्लैकबक ईवी ने एलन 3X - स्लीपर बस का किया अनावरण, 350 प्री-ऑर्डर किए प्राप्त तथा 1,000 बसों का रखा लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

ब्लैकबक ईवी इलेक्ट्रिक बस बाजार में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, जो लंबी दूरी की, प्रीमियम बसें प्रदान करने की अपनी मुख्य रणनीति पर दृढ़ता से कायम है। हमारी पहली एलन 3X, एक 13.5-मीटर सीटर बस, वर्तमान में कठोर आंतरिक सड़क परीक्षण से गुजर रही है। ये परीक्षण वाहन को उसकी सीमाओं तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्रदर्शन और स्थायित्व के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। प्रारंभिक परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं, और हम व्यापक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षणों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारे एलन 3X सीटर संस्करण की सफलता के बाद, हम एलन 3X के स्लीपर मॉडल के विकास की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। यह पहल लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बेहतर आराम के लिए भारतीय ग्राहकों की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करती है। हमारे अभिनव स्लीपर कोच डिज़ाइन में यात्रियों के आराम और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है, जो कई प्रमुख तरीकों से पारंपरिक मॉडलों से अलग है।

हमारी स्लीपर बसों में हेडरूम की सुविधा है, जिसमें प्रत्येक बिस्तर की लंबाई 1.8 मीटर है, ताकि यात्रियों को आराम से बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बस में 36 बिस्तर और लगभग 8 क्यूबिक मीटर का बड़ा सामान रखने की जगह है। एक बार चार्ज करने पर 300 किमी और 400 किमी की रेंज में उपलब्ध, ये विकल्प ऑपरेटर्स को उनकी विशिष्ट मार्ग आवश्यकताओं के आधार पर चुनने की अनुमति देते हैं। प्रीमियम गुणवत्ता वाले इंटीरियर में उच्च-स्तरिय सामग्री और फिनिश, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन तत्व और उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जो सभी एक शानदार और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं।

भारत में 13.5 मीटर का मल्टी-एक्सल इलेक्ट्रिक कोच लॉन्च करने वाली पहली कंपनी के रूप में, ब्लैकबक ईवी अपनी गति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि मल्टी-एक्सल (3-एक्सल) कॉन्फिगरेशन अपने बेहतर आराम और चिकनी सवारी के कारण लंबी यात्राओं के लिए आदर्श है। तीन-एक्सल सेटअप वाहन में वजन को अधिक समान रूप से वितरित करके, विशेष रूप से असमान सड़कों या मोड़ के दौरान स्थिरता को बढ़ाता है। इन लाभों पर ध्यान केंद्रित करके, हमारा लक्ष्य लंबी दूरी की यात्रा के लिए असाधारण आराम और विश्वसनीयता प्रदान करना है, जिससे इलेक्ट्रिक कोच सेगमेंट में हमारा नेतृत्व मजबूत होगा।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्लैकबक ईवी ने निजी परिवहन ऑपरेटर्स से मजबूत प्रतिक्रिया के साथ प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी है। आज तक हमने भारत में स्थित कई ग्राहकों और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौता ज्ञापन हासिल किए हैं, कुल मिलाकर 350 बसें, जिनमें सीटर और स्लीपर दोनों मॉडल शामिल हैं। हम संभावित ग्राहकों के साथ भी उन्नत चर्चा कर रहे हैं और साल के अंत से पहले और बुकिंग की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 1,000 बसों के लिए प्री-ऑर्डर स्वीकार करना है, उत्पादन शुरू करने के चार साल के भीतर इनका उत्पादन और वितरण करने की योजना है। प्री-ऑर्डर ग्राहक जो एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं, हम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पहली माइक्रो फेक्ट्री 2025 की तीसरी तिमाही तक चालू हो जाएगी, और 2025 के अंत तक पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह उन्नत उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करेगी कि हम अपनी



डिलीवरी प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करें और अपनी इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती मांग को पूरा करना जारी रखें।

हमारा ट्रेडमार्क सेवा मॉडल, EBAAAS यानी इलेक्ट्रिक बस एज ए सर्विस, व्यापक समर्थन के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेवा हमारे लिए एक प्रमुख फोकस है और इलेक्ट्रिक बस एज ए सर्विस वार्षिक रखरखाव अनुबंध यानी एमएसओ और वारंटी सहित कई विकल्प प्रदान करता है। EBAAAS में इलेक्ट्रिक बस परिवहन में संक्रमण के लिए आवश्यक

संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकल्प, एमएसओ, वारंटी और प्रशिक्षण शामिल हैं, जो सभी एक पैकेज में बंडल किए गए हैं। हमारा उद्देश्य बड़े के अपटाइम और परिचालन दक्षता को अधिकतम करते हुए इलेक्ट्रिक बसों में जाने से जुड़े जोखिमों को कम करना है।

इसके अतिरिक्त हम EBAAAS डिजिटल प्लैटफॉर्म मैनेजमेंट टूल प्रदान करते हैं, जो वास्तविक समय ट्रैकिंग, निरंतर चार्जिंग स्टेशन स्थान, ड्राइवर प्रबंधन प्रणाली

और सेवा शेड्यूलिंग जैसी उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है। यह टूल सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों के पास अपने इलेक्ट्रिक बस संचालन को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हों।

हमारे निरंतर नवाचारों और मजबूत ग्राहक फोकस के साथ, ब्लैकबक ईवी दुनिया भर में हमारे ग्राहकों के लिए अद्वितीय आराम, विश्वसनीयता और समर्थन प्रदान करते हुए, इलेक्ट्रिक बस उद्योग के परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

एनआईटी जमशेदपुर के छात्र शुरू करेंगे सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का स्टार्टअप



परिवहन विशेष न्यूज

पेट्रोल, डीजल और बैटरी से चलने वाले ई-वाहनों के बाद अब सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का जमाना आने वाला है। एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने इसका डिजाइन तैयार कर लिया है, जिसे अब लैब से निकालकर कमर्शियल बनाने की तैयारी की जा रही है। सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन को तैयार करने के बाद एनआईटी जमशेदपुर के छात्र इनसे बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पहल छात्र टीम रवेत ने की है। उनका प्रयास इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बाजार में उतारना और तकनीक को दूसरे स्तर पर ले जाना है। संस्थान के छात्र स्टार्टअप टूर पर अपनी खुद की कंपनी बनाकर इसे बाजार में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। संस्थान फंड देकर सहयोग करने की तैयारी है।

सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वाहन की ऊपरी सतह पर सोलर पैनल लगा है, जिससे वाहन हमेशा रिचार्ज रहेगा। इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी। बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज होकर चलती रहेगी। छात्रों के अनुसार, वर्तमान में बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली की जरूरत होती है और कहीं न कहीं बिजली का उत्पादन कार्बन उत्सर्जन का कारण बनता है, लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाला यह वाहन पूरी तरह से ग्रीन वाहन

होगा।

इस प्रोजेक्ट पर संस्थान के कई छात्र वर्षों से काम कर रहे हैं। इस हाइब्रिड सौर वाहन को तैयार करने में कई बैच के छात्रों ने अहम योगदान दिया है। अब इस प्रोजेक्ट को रवांता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से बाजार में उतारने की तैयारी है। इसे जमशेदपुर स्थित सोलर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनी बनाने की योजना है। प्रोजेक्ट के तहत सोलर इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में उतारकर ज्यादा से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी लेने का लक्ष्य है। इसके लिए छात्रों ने पहले साल में कंपनी के मुनाफे का भी अनुमान लगाया है, जिसके अनुसार कंपनी पहले साल में 30 लाख रुपये कमाएगी।

सोलर इलेक्ट्रिक वाहन को बाजार में उतारने के लिए छात्रों ने देश के 106 राष्ट्रीय उद्यानों और 567 वन्य जीव अभ्यारण्यों को लक्ष्य बनाया है। पहले चरण में इन वाहनों को सफारी के लिए बेचने की योजना है। छात्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। शुरुआती चरण में इसे सफारी के लिए बाजार में उतारा जाएगा। इसके बाद इसकी तकनीक को परिष्कृत कर अन्य क्षेत्रों के लिए भी लॉन्च करने की योजना है।

टीम रवांता के इस हाइब्रिड सोलर वाहन पर एनआईटी के 30 छात्र काम कर रहे हैं।

सैमसंग ने अपनी नवीनतम सॉलिड-स्टेट ईवी बैटरियों का किया प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

सैमसंग ने हाल ही में बैटरी प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सॉलिड-स्टेट बैटरी से संबंधित अपनी नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन करके उद्योग में हलचल मचा दी है।

दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित एसएनई बैटरी डे 2024 एक्सपो में कंपनी ने बताया कि उसकी पायलट सॉलिड-स्टेट बैटरी उत्पादन लाइन अब पूरी तरह से चालू हो गई है।

द इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग एसडीआई ने कहा, 'हमने 2027 तक बड़े पैमाने पर ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी का उत्पादन करने के लिए पिछले साल एक पायलट लाइन बनाई थी।' इसके अलावा बैटरी के प्रारंभिक बैच पहले ही परीक्षण के लिए ईवी निर्माताओं को वितरित कर दिए गए हैं।

सैमसंग एसडीआई ने कहा, 'हमने पिछले साल के अंत से लेकर इस साल की शुरुआत तक ग्राहकों को नमूने उपलब्ध कराए और हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।'

उल्लेखनीय बात यह है कि ये बैटरियां 600 मील की रेंज वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति प्रदान कर सकती हैं, 9 मिनट में चार्ज हो सकती हैं तथा इनका जीवनकाल 20 वर्ष का हो सकता है।

ये सॉलिड-स्टेट बैटरियां वर्तमान में अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में छोटी, हल्की और सुरक्षित होने की

उम्मीद है। इनमें ईवी उद्योग में क्रांति लाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

कंपनी ने बताया, 'सभी सॉलिड-स्टेट बैटरियां तरल घटकों को ठोस घटकों से बदलकर सुरक्षा बढ़ा सकती हैं। जब इन्हें मौजूदा उत्पादों के समान आकार के पैक में इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका वजन कम हो जाता है और ये कम जगह घेरती हैं।'

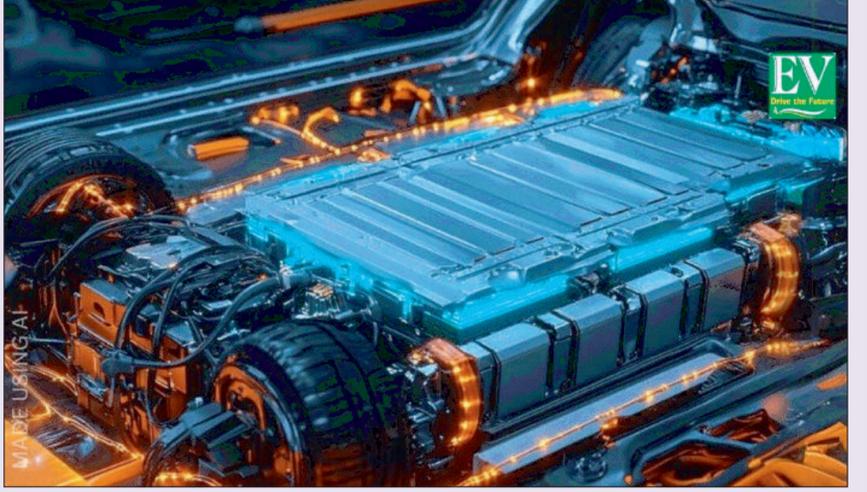
उच्च उत्पादन लागत के कारण इन बैटरियों का प्रारंभिक अनुप्रयोग 'सुपर प्रीमियम' ईवी सेगमेंट तक ही सीमित रहेगा। यहाँ 'सुपर प्रीमियम' सेगमेंट का मतलब है प्रति चार्ज लगभग 600 मील की ड्राइविंग रेंज। इसके अलावा सैमसंग प्रीमियम सेगमेंट के लिए हाई-निकेल एनसीएस उत्पाद पेश करेगा।

सैमसंग की ऑक्साइड सॉलिड-स्टेट बैटरी प्रौद्योगिकी में 500 Wh/kg का ऊर्जा घनत्व है, जो मुख्यधारा ईवी बैटरियों के 270 Wh/kg घनत्व से लगभग दोगुना है।

यह बढ़ा हुआ घनत्व वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को संभवतः दोगुना कर सकता है।

इसके अलावा, सैमसंग का 9 मिनट में चार्ज करने का दावा संभवतः बैटरी को 0% से 100% तक पूरी तरह चार्ज करने के बजाय 10% या 20% से 80% क्षमता तक चार्ज करने के मानक मीट्रिक को संदर्भित करता है।

यह प्रथा उद्योग में आम है क्योंकि बैटरी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की रक्षा के लिए चार्जिंग की गति आमतौर पर 80% के बाद



काफी धीमी हो जाती है।

ठोस अवस्था वाली बैटरियों पर अपने काम के अलावा सैमसंग अधिक किरफायती लिथियम आयन फॉस्फेट (एलएफपी) और कोबाल्ट-मुक्त बैटरियों के साथ-साथ लागत कम करने के लिए शुष्क इलेक्ट्रोड उत्पादन विधि का भी विकास कर रहा है।

सैमसंग एसडीआई ने जोर देकर कहा, 'हम न केवल लोकप्रिय और प्रवेश स्तर के खंडों में कीमत का मिलान करेंगे, बल्कि 2026 तक बड़े पैमाने पर ऐसे उत्पादों का

उत्पादन भी करेंगे जिन्हें 9 मिनट में तेजी से चार्ज किया जा सकेगा।'

ऐसा कहा जाता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित उपलब्धता एक बड़ी बाधा बनी हुई है। जबकि कुछ चीनी बैटरी निर्माता पहले से ही 5C या 6C चार्जिंग स्पीड, 480kW और यहाँ तक कि 600kW चार्जिंग स्टेशनों के बराबर की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है।

सभी बैटरी निर्माताओं का बैटरी की लंबी उम्र की पेशकश करने का स्पष्ट दृष्टिकोण

उल्लेखनीय है। CATL और अन्य बैटरी निर्माताओं ने पहले ही 20 साल की उम्र वाली बैटरी की घोषणा कर दी है, जिन्हें अक्सर 'मिलियन-माइलर बैटरी' कहा जाता है। सैमसंग का 'बैटरी की लाइफ को 20 साल तक बढ़ाने का विज्ञान व्यापक बाजार के रुझान के अनुरूप है।

सैमसंग की सॉलिड-स्टेट बैटरी की प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन कंपनी को चीनी निर्माताओं के प्रभुत्व वाले प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आगे बढ़ना होगा।

सिट्रोएन बैसेल्ट भारत में हुई पेश, शानदार डिजाइन और लगजरी इंटीरियर से लैस

परिवहन विशेष न्यूज

कार निर्माता कंपनी Citroen अपनी 5वीं कार Basalt कूपे SUV को आज पेश किया है। इसमें काफी खुश खास फीचर्स दिए गए हैं। जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले 10.25 इंच की टचस्क्रीन सिस्टम वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड समेत 6 एयरबैग जैसे बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं। वहीं कंपनी अपनी इस गाड़ी को लेकर दावा कर रही है कि यह 18 किमी/लीटर का माइलेज देगी।

नई दिल्ली। Citroen ने अपनी नई Basalt SUV-कूपे के भारतीय मार्केट में पेश किया है। कंपनी ने Citroen Basalt के कुछ टीजर पहले ही जारी किए थे और इसके एक्सटीरियर का खुलासा भी पहले हो चुका है, लेकिन अब इस SUV-कूपे के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन का खुलासा किया गया है। इसे कंपनी आपस में किसी समय लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास दिया गया है।

Citroen Basalt का कैसा है एक्सटीरियर ?

इसका डिजाइन C3 Aircross कॉम्पैक्ट SUV

काफी हद तक मिलता जुलता है। आगे की तरफ V-आकार के स्फिंट LED DRLs और स्फिंट ग्लिल दिया गया है। इसको अनूठा रूप देने के लिए बम्पर डिजाइन में बदलाव किया गया है। रूप कूफलाइन और डुअल-टोन फिनिश एलॉय व्हील्स दिया गया है। गाड़ी के पीछे की तरफ रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट्स और ब्लैक-आउट बम्पर और सिल्वर स्क्रिड प्लेट दी गई है।

कैसा है Citroen Basalt का इंटीरियर ?

बेसाल्ट का केबिन C3 एयरक्रॉस से मिलता-जुलता है। इसमें काफी शानदार डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले और एसी वेट के लिए समान डिजाइन दिया गया है। सिट्रोएन ने इसे सफेद लेदरेट अपहोल्ट्डी दी है। बेसाल्ट की रियर सीट बेस 87 मिमी आगे बढ़ती है ताकि बेहतर अंडरथाई सपोर्ट मिल सके। इसके साथ ही रियर हेडरेस्ट, एक स्वालित क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इसके अलावा गाड़ी में 10.25 इंच की टचस्क्रीन



सिस्टम, केबिन कम्फर्ट में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMS, स्टीरिंग-माउंटेड कंट्रोल, क्रूच कंट्रोल, 470L लगेज कैरी करने की क्षमता जैसे फीचर्स से लैस किया गया है।

Citroen Basalt का दमदार है इंजन Basalt को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन 82 PS को पावर

और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल वाला इंजन 110 PS की पावर और 205 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है। माइलेज की बात करें तो NA पेट्रोल के लिए 18 किमी/लीटर, टर्बो MT के लिए 19.5 किमी/लीटर और टर्बो AT के लिए 18.7 किमी/लीटर मिलेगा।

डॉक्टरों और इंजीनियरों से परे शुद्ध विज्ञान में करियर तलाशना



विजय गर्ग

तकनीकी-व्यावसायिक भूमिकाएँ तकनीकी उत्पादों को बढ़ावा देने, प्रदर्शित करने के लिए जीवन विज्ञान संगठनों के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पादों को सही तरीके से रखने के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता था - क्योंकि उन्होंने अपने शोध के दिनों में इसी तरह के उत्पादों का उपयोग किया होगा। उन्हें विभिन्न वैज्ञानिकों से मिलने और उनकी चुनौतियों को समझने और उचित समाधान देने में उनका समर्थन करने का लाभ मिलता है।

जब एक सुरक्षित करियर के लिए पेशेवर डिग्री चुनने की बात आती है, तो भारत में अभी भी कई लोग शुद्ध विज्ञान का अध्ययन करने के बजाय डॉक्टर या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम लेना पसंद करते हैं। हालाँकि, क्या आप शुद्ध विज्ञान का अध्ययन करने के बाद कई करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं? इस लेख में, वैकट कौशिक पुल्ला, जो एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक हैं और मर्क में वरिष्ठ प्रबंधक वाणिज्यिक विपणन के रूप में काम करते हैं, हमें एक वैज्ञानिक होने के लाभों और चुनौतियों के बारे में बताते हैं। अंश: 1. एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक के रूप में, शुद्ध विज्ञान में करियर के कौन से विकल्प हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए? शुद्ध विज्ञान में तलाशने के लिए कई पहलू हैं, और यह सब आपके रुचियों की खोज के बारे में है। इन दिनों, करियर में उन्नति के लिए बहु-विषयक कौशल सेट का होना महत्वपूर्ण है। मौजूदा कौशल और प्रौद्योगिकियों अचलित होती जा रही हैं, इसलिए चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, निरंतर उन्नयन आवश्यक है। एआई द्वारा नीरस कार्यों को संभालने के साथ, रचनात्मकता और अद्वितीय दृष्टिकोण अलग दिखने की कुंजी हैं। शुद्ध विज्ञान में करियर विकल्पों में शामिल हैं: अनुसंधान वैज्ञानिक यह संभवतः शुद्ध विज्ञान स्नातकों के लिए सबसे स्पष्ट विकल्पों में से एक है। अनुसंधान वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करके, सरकारी अनुसंधान संस्थानों और फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान जैसे निजी उद्योगों की प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। वे प्रयोग करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और वैज्ञानिक खोजों में योगदान देते हैं। डेटा वैज्ञानिक बड़े डेटा और एनालिटिक्स के बढ़ने के साथ, ऐसे डेटा वैज्ञानिकों की मांग बढ़ रही है जो जटिल डेटा सेट को व्याख्या करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटेशनल तकनीकों को लागू कर सकते हैं। शुद्ध विज्ञान स्नातकों के पास अक्सर मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल और गणितीय और सांख्यिकी के साथ उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करती है, जिससे उन्हें अपनी खुद की कंपनियों शुरू करने, नई तकनीक विकसित करने या उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करने की अनुमति मिलती है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि शुद्ध विज्ञान का अध्ययन न केवल इन विशिष्ट करियर पथों के द्वार खोलता है बल्कि व्यक्तियों को आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और आम जनता के बीच अंतर को पाटने, दर्शकों को महत्वपूर्ण खोजों और विकासों के बारे में सूचित

करने और शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेटेंट परीक्षक पेटेंट परीक्षक यह आकलन करते हैं कि क्या आविष्कार उद्ये योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और नवाचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुद्ध विज्ञान की पृष्ठभूमि इस पेशे के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है। तकनीकी-व्यावसायिक भूमिकाएँ तकनीकी उत्पादों को बढ़ावा देने, प्रदर्शित करने के लिए जीवन विज्ञान संगठनों के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पादों को सही तरीके से रखने के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता था - क्योंकि उन्होंने अपने शोध के दिनों में इसी तरह के उत्पादों का उपयोग किया होगा। उन्हें विभिन्न वैज्ञानिकों से मिलने और उनकी चुनौतियों को समझने और उचित समाधान देने में उनका समर्थन करने का लाभ मिलता है। विज्ञान शिक्षा और आउटरीच शुद्ध विज्ञान स्नातक स्कूलों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान शिक्षकों के रूप में करियर बना सकते हैं, भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित और सलाह दे सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट (सीआरए) फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों में, सीआरए प्रोटोकॉल और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नैदानिक परीक्षणों की देखरेख करते हैं। शुद्ध विज्ञान की पृष्ठभूमि नैदानिक अनुसंधान के अंतर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान प्रदान करती है। गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) विशेषज्ञ क्यूए/क्यूसी विशेषज्ञ सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सिस्टम गुणवत्ता मानकों और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में, वे उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमिता और नवाचार: कई शुद्ध विज्ञान स्नातकों में उद्यमशीलता की आकांक्षाएँ और नवाचार करने की क्षमता होती है। सरकार प्रारंभिक बीज अनुदान के साथ उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करती है, जिससे उन्हें अपनी खुद की कंपनियों शुरू करने, नई तकनीक विकसित करने या उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करने की अनुमति मिलती है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि शुद्ध विज्ञान का अध्ययन न केवल इन विशिष्ट करियर पथों के द्वार खोलता है बल्कि व्यक्तियों को आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल से भी सुसज्जित करता है जिन्हें विभिन्न उद्योगों में अत्यधिक महत्व

दिया जाता है। जैसे-जैसे दुनिया तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ रही है, कुशल शुद्ध विज्ञान स्नातकों की मांग बढ़ती रहेगी, जिससे यह एक आशाजनक और फायदेमंद करियर विकल्प बन जाएगा। 2. वैज्ञानिक बनने की चुनौतियाँ क्या हैं? वैज्ञानिक बनना एक पुरस्कृत कार्य है लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी आती हैं जिनसे वैज्ञानिक बनने के इच्छुक लोगों को अवगत होना चाहिए: शिक्षण और प्रशिक्षण वैज्ञानिक बनने में आम तौर पर स्नातक, स्नातकोत्तर और अक्सर पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करना शामिल होता है। इसके लिए समर्पण, दृढ़ता और एक मजबूत शैक्षणिक नींव की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धी वातावरण सीमित संसाधनों और योग्य आवेदकों की उच्च संख्या के कारण अनुसंधान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। समय और धैर्य वैज्ञानिक प्रारूप प्रदान करना अक्सर लंबे समय तक प्रयोग, डेटा विश्लेषण और लेखन की आवश्यकता होती है। प्रगति धीमी हो सकती है, सफलताएँ प्राप्त करने में वर्षों या दशकों का समय लाग सकता है। फंडिंग और संसाधन अनुसंधान के संचालन के लिए उपकरण, सामग्री और कभी-कभी कर्मियों के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त फंडिंग सुरक्षित करना एक निरंतर चुनौती हो सकती है, खासकर शुरुआती करियर शोधकर्ताओं के लिए। प्रकाशन और सहकर्म समीक्षा करियर में उन्नति और पहचान के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित करना आवश्यक है। सहकर्म समीक्षा प्रक्रिया कठोर और कभी-कभी व्यक्तिपरक हो सकती है, जिसके लिए दृढ़ता और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। नवाचार और पुनरुत्पादकता को संतुलित करना नवोन्मेषी अनुसंधान को आगे बढ़ाने और परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वैज्ञानिक अखंडता और कठोरता बनाए रखना आवश्यक है लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में अस्थिरता अन्य व्यवसायों की तुलना में विज्ञान में करियर पथ कम पूर्वानुमानित हो सकते हैं। अल्पकालिक अनुबंध, पोस्ट-डॉक्टोरल पद और अनुसंधान के अवसरों के लिए स्थानांतरित होने की आवश्यकता आम है, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा होती है। कार्य संतुलन वैज्ञानिक अनुसंधान की मार्गात्मक प्रकृति कार्य-जीवन संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो लंबे

समय, समय सीमा और प्रकाशित करने का दबाव तनाव और जलन का कारण बन सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, विज्ञान में करियर ज्ञान, नवाचार और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लचीलेपन, खोज के प्रति जुनून और वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। 3. एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक होने के नाते, आप एक वाणिज्यिक विपणन प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। कृपया अपना जॉब प्रोफाइल विस्तृत करें। मर्क में एक वाणिज्यिक विपणन प्रबंधक के रूप में, मेरा काम वैज्ञानिक नवाचारों और उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका व्यावसायिककरण करने के इर्द-गिर्द यूनाता है। यहाँ कुछ प्रमुख भूमिकाएँ दी गई हैं: योज्य जिम्मेदारियाँ: उत्पाद स्थिति निर्धारण और ब्रांडिंग: अपने उत्पादों को बाजार में प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना। सम्बन्धक संदेश और ब्रांडिंग प्रबंधन करना जो हमारे लक्षित दर्शकों को पसंद आए। विपणन अभियान: डिजिटल मार्केटिंग और सम्मेलनों जैसे विभिन्न चैनलों पर मार्केटिंग अभियानों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। ग्राहकों से मुलाकात कर उनकी जरूरतों और बाजार के रुझान को समझना। प्रचार सामग्री विकसित करने और कार्यक्रम चलाने के लिए रचनात्मक टीमों के साथ सहयोग करना। डेटा विश्लेषण: विपणन अभियानों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना। वर्कफ्लो अंतराल की पहचान करना और लक्षित अभियान विकसित करना। बिक्री समर्थन: बिक्री बढ़ाने में उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रभावी उपकरण, सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बिक्री टीम के साथ मिलकर काम करना। ग्राहक वचनबद्धता: वेबिनार, रोड शो और सम्मेलनों के माध्यम से प्रमुख राय वाले नेताओं के साथ संबंध बनाना। बाजार का विकास: मौजूदा उत्पादों के लिए नए बाजार अवसरों और संभावित अनुप्रयोगों की पहचान करना। बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना। कुल मिलाकर, मेरी भूमिका वैज्ञानिक नवाचार और व्यावसायिक सफलता के बीच अंतर को पाटती है, यह सुनिश्चित करती है कि हमारे उत्पाद ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

संपादक की कलम से

आरक्षण के उप-वर्गीकरण

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में ही आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला सामाजिक न्याय के लिए 'मील का पथ' साबित हो सकता है। मंडल के बाद यह दूसरा ऐतिहासिक फैसला है। 'मील का पथ' तभी साबित हो सकता है, जब क्रीमीलेयर वाला फैसला लागू किया जाएगा। आरक्षण में उप-वर्गीकरण का आर्थिक राज्य सरकारों को दिया गया है। यह अभी तक राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित था। संसद में ही प्रस्ताव पारित कर, किसी भी जाति को, आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता था अथवा जाति को आरक्षण से बाहर भी किया जा सकता था। बहरहाल वह अधिकार यथावत रहेगा, लेकिन एससी और एसटी अपने आरक्षण के कोटे में, देवी-कुचली, पिछड़ी, विपणन जातियों का, उप-वर्गीकरण कर सकेगा। फिलहाल दलित और आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में क्रमशः 15 फीसदी और 7.5 फीसदी आरक्षण हासिल है। संविधान पीठ के दो कथन महत्वपूर्ण हैं। एक, एससी-एसटी के कोटे में कुछ जातियों का उप-वर्गीकरण करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता। समानता का सिद्धांत यथावत रहेगा। दूसरे, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित कर देना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक पहुँच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई ने एससी-एसटी पर भी, ओबीसी की तरह, 'क्रीमीलेयर' लागू करने की बात कही है। यह विवादास्पद मुद्दा बन सकता है। अवसरों और संभावित अनुप्रयोगों की पहचान करना। बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना। कुल मिलाकर, मेरी भूमिका वैज्ञानिक नवाचार और व्यावसायिक सफलता के बीच अंतर को पाटती है, यह सुनिश्चित करती है कि हमारे उत्पाद ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।

कम होने लगेगा। बहरहाल संविधान पीठ ने कहा है कि सरकारी को एससी-एसटी श्रेणी के बीच 'क्रीमीलेयर' की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने की नीति जरूर तैयार करनी चाहिए। यह अवधारणा भी स्पष्ट होनी चाहिए। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण उनकी सालाना आय के आधार पर तय किया जाता है। क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रुपए सालाना है। यानी करीब 67,000 रुपए महीना। यह वर्ग विपणन कैसे हो सकता है? दूसरी ओर वे भारतीय भी हैं, जो 375 रुपए रोजाना कमाने में भी असमर्थ हैं। बेहतर होता कि क्रीमीलेयर पर भी न्यायिक फैसला सुनाया जाता। बहरहाल फैसले के जोखिम भी सामने आने लगे हैं। पर्याप्त संभावना है कि एससी-एसटी अब एक समूह नहीं रह जाएगा। उनके भीतर ही अलग-अलग वर्ग खड़े हो जाएंगे और फिर उनसे जुड़ी नई राजनीति उबलने लगेगी। केंद्र सरकार में ही एनडीए की सहयोगी लोजपा (रामविलास) ने फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है, ताकि एससी-एसटी वर्ग में भेदभाव न हो और वे कमजोर न पड़ें। चूँकि इसे राज्य लागू कर सकेगा, लिहाजा यह सवाल मौजूद है कि कब तक यह निर्णय लागू किया जा सकेगा। एससी-एसटी की गणना अतिव्यवस्था, लिहाजा जातीय जनगणना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकारें विशेषज्ञ-पैनल बना सकती हैं। विशेषज्ञ और डाटा के जरिए प्रायोगिक कौनसी जाति सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी है और उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। पीठ ने 2004 में 'इंवा चिन्ना-बेनाल आंध्र' वाले मामले में दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकार तय आरक्षण में उप-वर्गीकरण नहीं बना सकती। ताजा फैसला पंजाब का है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था कि राज्य में एससी-एसटी आरक्षण में 50 फीसदी आरक्षण, पहली प्राथमिकता के तहत, वार्षिक और महत्वपूर्ण सेवाओं को मिलेगा। पंजाब उच्च न्यायालय ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था।

कविता

कहने को बहुत कुछ है

कहने को बहुत कुछ है पर कह नहीं पा रहे। दिल में भरा है गुबार, उसे सह नहीं पा रहे। कब तक बोझ लिए, रमते व धूमते रहोगे। ज्यादा मत बहलाओ, मुस्कुराकर ना सहलाओ। आने भी दो बाहर उसे, तुम्हें सुकून ही मिलेगा। मचा था जो तहलका, वह जरूर होगा हक्का। बस जुबा खोलने की देरी है, सारी कायनात तेरी-मेरी है। इन अनमोल अशकों को, तुम ना बहाना अकेले में। अब चाहे मुझे मिलो, किसी भीड़ या मही में। इंतजार मत रहे है बाहें, बस फेरना मत निगाहें। क्योंकि, कहने को बहुत कुछ है बहुत कुछ है।

कविता: फ़िक्र

घर से निकला आदमी, खुशनुमा चेहरा लिए दिनचर्या में हुआ लीन। भले ही इस दौरान, सुख वैग गया हो छीन। गर आ जाए एक कॉल, पूछ ले आर्घ्यांगीं हाला। तब आर एस कुनभरी आवाज, रकैसे हो, कहाँ हो और घर कब तक आओगे। थकान की निद्रा को चीरती हुई मिटास। रपउपनेपनर और रफ़िक्रर का, दिलाती है एहसांस। तब बरबस ही निकलता, संजय से एक ही संवाद रअरे अरे हमसपर इतने सवालर। बरबस ही निकला जवाब, रमै रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मन ही मन वो बुदबुदाया,

सच कितनी रफ़िक्रर है तुम्हें मेरे घर आने की। -संजय एम. तारणेकर (कवि, गायक व समीक्षक) द्वाहाटसए नंबर 9826025986

विजय गर्ग

तपती गर्मी के बाद किसी शाम मेघ की गर्जना के साथ अगर बारिश होने लगे, तो बहुत सारे लोग घर में बंद होकर बरसात के गुजर जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसे माहौल में जरा खिड़की से बाहर झांका जाए तो दूर तक फैले खेत और भगती प्रकृति किसी भी प्रकृति प्रेमी के मन को बांध ले सकती है। जिस तरह जीवन के रंग बदलते रहते हैं, उसी तरह जीने के लिए मौसम का बदलना भी जरूरी है। बदलते मौसम के लिए हमारा अनुकूलन हमारे अस्तित्व को परखता है। हम हैं और हम अपने होने को प्रत्येक स्थिति में साबित भी करते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति से हमारे समन्वय का एक प्रतीक बनता है। ठीक इसी प्रकार जीवन चाहे जैसा भी हो, अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलता। सामान्य लोगों के जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं रहता। देखा जाए तो जीवन के दो पक्ष ही हम पर हावी रहते हैं- एक, जीविका की जदोजहद और दूसरा संवेगात्मक आधार। एक मध्यमवर्गीय परिवार न जाने कितनी आंधियों को इन्हीं दो पृष्ठभूमियों पर झेलता जाता है। मगर जिजीविषा नहीं मरती। शायद यही है जीवन की मूल - जिजीविषा। हम जीना पसंद करते हैं। परिस्थितियों से हारकर हम अगर जीवन को हथकौड़ी में धरती कब की समाप्त हो गई होती। हम गिरते हैं, चोट खाते हैं, पर फिर उठते जरूर हैं, क्योंकि हमारे लिए रुकने का मतलब मृत्यु है। उठना ही है, चलना ही है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ना ही है- यही मायावचन है। ठीक यही बात हमें बरसात का मौसम भी सिखा



जाती है। जब यह धरती ऊष्णता और घुटन से बोझिल हो जाती है तो वर्षा की बूंदें आकर इसके अंतर को धो जाती हैं। तब धूल जाते हैं सारे दुख, सारे पाप, तन और मन पर पड़ी हुई गंदगी। नई निखरती पल्लवों के साथ फिर उलसित हो उठती है धरा... बोलने लगती है बीज भविष्य के हरियाली की। ठीक इसी तरह हम इंसानों को भी इस बारिश के पानी में भीगकर अपने तन और मन के क्लेश, कुंठा, द्वेष, सबका निस्तारण कर देना चाहिए। ठंड, गर्मी और बरसात - ये बदलते मौसम आते-जाते रहते हैं, लेकिन हर बार हम इंसानों के समुदाय को कुछ न कुछ सीखते दे जाते हैं। इस धरती पर हम इंसान ही एकमात्र ऐसे जीव हैं, जिसका दावा है कि उसे सही और गलत

की पहचान होती है। इस वसुधा को एक कुटुंब मानकर निस्वार्थ भाव से जीवन की धारा में बहते जाना ही मनुष्य का मकसद होना चाहिए। हम ऐसी प्रजाति हैं, जो जीवन देने में विश्वास करते हैं, लेकिन आजकल के समाज में 'स्व' का भाव ज्यादा विस्तारित हो गया है। आत्मकेंद्रित हो मनुष्य आज एक दूसरे का ही प्रतिरोधी बन गया है और मनुष्य के लिए प्रस्तुत हो जाता है, जिसमें उसका स्वार्थ हो। मन भाव दूषित हो गए हैं। द्वेष, घृणा, नफरत, बदला आदि की भावना का प्रदूषण हो गया है। भावनाओं की इस फैलती विकृति ने जीवन का मूल ही खो दिया है। सुष्टि

के बनाए धरती का पर्याय प्रेम और त्याग है। ये विचार अंतिम सांसें गिन रही हैं। हम मनुष्यों को चाहिए कि इन कल्पित भावों को धोकर जीवन के जीवत पक्ष पर फिर से काम करें। हमारा पोषण हमारे अन्न से होता है, लेकिन हमारी अंतस का पोषण हमारे भाव से होता है। अगर हम अपने अंदर विपरीत सोच को विकसित कर लेंगे तो हमारे जीवन का विकास भी विपरीत ही होने लगेगा। हम दूसरों को घाव देकर सोचते हैं कि हमने बदला ले लिया। दूसरों के साथ छल करके हम खुश होते हैं कि किसी को मुर्ख बना दिया गया, लेकिन हम यह नहीं समझना चाहते कि वह घाव, वह छल पहले हमारी आत्मा को चोटिल करेंगे और हम

पतन की ओर मुखातिब हो जाएंगे। आज की तारीख में हो रहे दंगा-फसाद इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का दिमाग कितना भ्रष्ट हो चुका है। इन असांजकारियों को करते हुए वह इतना भी नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। उसकी आत्मा इतनी दूषित हो चुकी है कि किसी की हानि करते हुए उसे सुख की प्राप्ति होती है। वर्तमान प्रसंग में देखा जाए तो आसपास हो रहे अमानवीय कृत्यों ने लोगों की जड़ों को तोड़ा है। मानव अपने मूल प्रवृत्ति से उखड़ता जा रहा है। जीने के लिए जिजीविषा और आत्मा की उच्छ्वा दोनों पर ही प्रहार किए गए हैं। बात बस यह है कि यह खुद मनुष्य ही तय कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में अग्रसर होना है, सुधरना का कोई वक्त नहीं होता। अब भी समय नहीं बीत गया है। अगर आज भी हम यह निर्णय ले लें कि हमें अपने अंदर की बुराई को मारकर अच्छाई को जिंदा करना है तो भी जीवन सुंदर बन सकता है। हमें सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे- अपने कुत्सित मन के आवेग या अपनी आत्मा की निर्मलता। हमारा जीवन बरसात की बूंदों की तरह ही है। अपने अंदर स्वच्छता को महत्व देते हुए बढ़ना ही इस जीवन का सार है। शायद इसी के निमित्त वर्षा का भी आगमन होता है। अपने जीवन को स्वच्छ बनाने के साथ साथ अपनी आत्मा को सुंदर बनाकर प्रकृति के आंगन में रिमझिम बूंदों का आनंद लेना ही जीवन है।

सीखने का विकास

विजय गर्ग

इसके लिए निर्णय, संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और नए विचारों को आत्मसात करने की दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है वास्तविक दुनिया में बातचीत करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वास्तविक जीवन की बात आती है तो बचपन की बहुत सी प्रारंभिक सीखों में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चे को कई सिद्धांत सिखाए जाते हैं जो बड़े होने पर बिल्कुल अव्यावहारिक हो जाते हैं। आम तौर पर, एक बच्चे से कहा जाएगा कि वह अपने माता-पिता को बताए बिना कभी कुछ न करे, जबकि वास्तविक जीवन में यह न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है। सच तो यह है कि बचपन की सीख बुनियादी बातों के बारे में होती है; जैसे-जैसे कोई आगे बढ़ता है, वह इसे संशोधित या अंशकित करना सीखता है। इसका संबंध बच्चे के दिमाग और कुछ सिद्धांतों की स्थापना से है जिन्हें जीवन के अनुभव परिभाषित या संशोधित कर सकते हैं। एक बच्चे को समानांतर रेखाओं के बारे में सिखाने के मामले पर विचार करें। बच्चे को सिखाया जाता है कि समानांतर रेखाएँ ऐसी रेखाएँ होती हैं जो कभी नहीं मिलती। यह उसके उद्देश्यों के

लिए काफी अच्छा है। जैसे-जैसे कोई परिपक्व होता है और कुछ वर्ष बढ़ता है, वयस्कता में परिवर्तन करने वाला बच्चा सीखता है कि समानांतर रेखाएँ मिलती हैं, लेकिन वे 'अनंत' पर मिलती हैं। ऐसे ही उदाहरण अन्याय भी उद्धृत किये जा सकते हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर एक सरल प्रस्ताव यह है कि सीखना सीखने वाले की क्षमता और क्षमता से संबंधित है। एक ही सिद्धांत में कई संशोधन या परिवर्तन भी हो सकते हैं। जैसे-जैसे कोई वयस्कता में आता है, वह जीवन के बारे में कई अन्य पेचीदगीयों सीखता है, और उनमें से कई को केवल अनुभव के माध्यम से ही दोबारा सीखा जा सकता है। यहाँ व्यक्ति को निरंतर सीखने और आत्मसात करने की क्षमता को तेज करने की आवश्यकता है। आम तौर पर, वयस्क, जैसे-जैसे जीवन से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, और कई अन्य लोगों के साथ सह-अस्तित्व की स्पष्ट आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का निर्णय यह तय करने के लिए निर्णायक बन जाता है कि सत्य क्या है और उसे कहीं स्पष्ट रहना है या उससे होकर गुजरना है। वयस्क शिक्षा इसी के बारे में है, और यह एक आजीवन आवश्यकता है जिसे प्रत्येक चरण में महसूस किया जाता है। कभी-कभी अजीब स्थितियों

उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर यदि कोई कहावतों/कहावतों/लोक कहावतों और यहाँ तक कि बड़ों के ज्ञान के माध्यम से सीखता है। इसके एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो सकती है। संस्कृत में एक कहावत है 'रसत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् मतलब है, सच बोलो, लेकिन सुखद बोलो। अगर कोई सच कड़वा है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है।' यह वांछनीय है या नहीं यह एक विवादास्पद मुद्दा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अन्य कहावतें ऊपर उद्धृत रूप से दो अलग-अलग संदर्भों में हैं और दो अलग-अलग अर्थ रखते हैं। दोनों के बीच विरोधाभास का तत्व है। यहाँ पर वयस्क शिक्षा अपना एक विशेष आवरण प्राप्त करती है। वह विशेष चीज क्या है यह अनुवादित, इसका विषय है। कुछ लोग जो बचपन में बार-बार इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, उन्हें केवल सच बोलने की आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे बातचीत में आक्रामक हो जाते हैं।

ऐसा उनकी बदनियती के कारण नहीं, बल्कि उनका अंदाज ही 'आक्रामक' हो गया। इस तरह के आपत्जनक व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिरकार, व्यवहारकुशलता एक ऐसी चीज है जो वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं है, यह जीवन के लिए आवश्यक है। व्यवहारकुशलता होने का मतलब झूठ बोलना या असत्य बोलना नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है और भावनाएँ। यह पहचानने के महत्व को भी बढ़ाता है कि सभी इनपुट बेहतर और बेहतर व्यवहार में योगदान करते हैं। ऐसी स्थिति बनाना आवश्यक है जिसमें सभी को लाभ हो और बेहतर वातावरण स्थापित हो। यदि कुंदता सुधार में गिरावट पहुँचाती है, तो इससे जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, जो किसी भी कार्यवाही का उद्देश्य नहीं हो सकता है। स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सीखना कई परतों वाली एक जटिल घटना है। इसके लिए निर्णय संवेदनशीलता और दूरदर्शिता की आवश्यकता है। उपरोक्त किसी भी रिश्ते के अभाव में, उनमें समझौता हो सकता है। आखिरकार, यदि रिश्ता ही खत्म हो जाए, तो कोई पूछ सकता है: इनपुट किस बारे में है? यह मुद्दा जीवन जीने के लिए मौलिक है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक मिलनसार जानवर है, और जीवन जीने के लिए सामूहिक अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए सीखना एक आजीवन अभ्यास है जिसमें निरंतर भागीदारी और विकसित होने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए बाहरी इनपुट बेशक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसका अंतरिककरण मूल है। दुर्भाग्यवश, जहाँ शिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, वहीं उलना ही ध्यान सीखने की प्रक्रिया के तरीकों पर भी दिया गया है। वास्तव में सीखने की क्षमता और सीखने के तरीकों की निश्चित सीमाएँ हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे पहले की तुलना में अधिक व्यापक रूप से मान्यता देने की आवश्यकता है, खासकर जब से यह सीखने के बड़े सिद्धांतों में एकीकृत नहीं होता है। वास्तव में, किसी को इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सीखने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण कब और कैसे मौलिक हो जाता है। संक्षेप में, सीखने की निरंतर प्रकृति और उस सीखने को जीवित रखने में अपनी केंद्रीय भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक केवल प्रक्रिया में मदद कर सकता है लेकिन किसी शिक्षार्थी की सीख का स्थान नहीं ले सकता।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार

72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजिम को चुना, क्या अब पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करेगी सरकार?

परिवहन विशेष न्यूज

नई टैक्स रेजिमे व ओल्ड टैक्स रेजिमे आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कुल 7 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल किया। इसमें से 72 फीसदी करदाताओं ने न्यू टैक्स रिजिम को चुना। इससे सवाल उठता है कि क्या अब सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म कर देगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रिजिम को पेश किया था। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को जटिलताओं को दूर करके उसे आसान बनाना था। इसमें आयकर से छूट की सीमा अधिक थी, लेकिन करदाता निवेश या किसी और मध्यम से अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं ले सकते थे। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ स्टैडिडिडिशन को लिमिट भी बढ़ा दी। इससे यह कर व्यवस्था और भी आकर्षक बन गई।

72 फीसदी ने नई कर व्यवस्था को चुना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। इनमें से

5.27 करोड़ ने नई और 2.01 करोड़ ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना। इसका मतलब है कि 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई और 28 फीसदी ने पुरानी कर व्यवस्था से अपना रिटर्न दाखिल किया।

इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सरकार ने पिछले साल न्यू टैक्स रिजिम की डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया था। इसका मतलब कि अगर आप खुद से कोई टैक्स रिजिम नहीं चुनते, तो आपका रिटर्न ऑटोमैटिक नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल होगा। लेकिन, टैक्सपेयर्स को पूरी छूट थी कि वे अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स रिजिम चुन सकें।

न्यू टैक्स रिजिम को क्यों चुन रहे करदाता

नई कर व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है इसका सरल होना। अगर आप पहली बार भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप न्यूज ऑटोकल या फिर यूट्यूब वीडियो के सहारे आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें नियम-कायदों की अधिक झंझट नहीं है। इसने कई कठौतियों और छूटों से जुझने को बौते जमाने की बात बना दिया है। यह चीज टैक्सपेयर्स को काफी पसंद आ रही है।

भारतीय उद्योग परिषद (CII) का कहना है कि नई कर व्यवस्था के स्लैब में टैक्स देनदारी की स्पष्ट और सीधी गणना होती है। इससे समय की काफी बचत होती है। साथ ही, न्यूटिओ और गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। कई स्रोतों से आय कमाने वाले करदाताओं को पहले रिटर्न दाखिल करना मुश्किल काम लगता था। नई कर व्यवस्था ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया है।



OLD Vs New Tax Regime

आपके लिए कौन-सा है बेहतर

उसका इरादा ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म करने पर है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि दो टैक्स रिजिम होने से करदाताओं की उलझनें बढ़ रही हैं। सरकार का न्यू टैक्स रिजिम लाने का मकसद ही टैक्सपेयर्स की उलझन कम करना था। ऐसे में दो कर व्यवस्थाएं रहने का का कोई तुक नहीं बनता।

की कई उलझनें अपनेआप खत्म हो जाएंगी। वे आईटीआर भी ज्यादा आसानी से फाइल कर पाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकारी अभी कुछ और करदाताओं के नई कर व्यवस्था में सिक्चर करने का इंतजार कर सकती है। खासकर, अधिक इनकम वालों के। फिर वह पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करके न्यू टैक्स रिजिम को आगे बढ़ाएंगी।

काम दो 25 केवी टैक्सन सबस्टेयन और उससे जुड़ी अन्य चीजों का निर्माण करना है। टैक्समैको के वाइस चेयरमैन इंद्रजीत मुखर्जी ने कहा, 'रथ ऑर्डर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।' उन्होंने कहा कि कंपनी आशावादी है और उम्मीद करती है कि यह उसकी ग्रोथ में योगदान देगा।

एक साल में 150 फीसदी का रिटर्न देने वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, शेयरों पर दिखेगा असर

टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) से 243 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसका असर टैक्समैको के शेयरों पर दिख सकता है। टैक्समैको के शेयरों में पिछले एक साल में 150 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। टैक्समैको रोलिंग स्टॉक हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण स्टील कार्टिंग और रेल इपीसी पुल और अन्य स्टील इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के व्यवसाय में शामिल है।

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक साल में 150 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। अब कंपनी को मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) से 243 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। टैक्समैको को यह ऑर्डर महाराष्ट्र में दो रूट पर पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है।

टैक्समैको की हायर-स्पेशलाइज्ड EPC डिविजन- ब्राइट पावर पर इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी होगी। वह पावर सप्लाई प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टालेशन और टैस्टिंग का काम करेगी। कंपनी के मुताबिक, उसका

काम दो 25 केवी टैक्सन सबस्टेयन और उससे जुड़ी अन्य चीजों का निर्माण करना है।

टैक्समैको के वाइस चेयरमैन इंद्रजीत मुखर्जी ने कहा, 'रथ ऑर्डर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।' उन्होंने कहा कि कंपनी आशावादी है और उम्मीद करती है कि यह उसकी ग्रोथ में योगदान देगा।

टैक्समैको के शेयरों का हाल

टैक्समैको के शेयर केंद्रीय बजट के बाद से काफी सुस्त पड़े हैं, क्योंकि इसमें रेलवे सेक्टर के लिए बड़ा और खास एलान नहीं हुआ। पिछले एक महीने में टैक्समैको ने सिर्फ 3 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों से निवेशकों को 28 फीसदी का मुनाफा हुआ। लेकिन, पिछले एक साल की बात करें, तो टैक्समैको ने 151.22 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।

ब्रोकरेज भी टैक्समैको भी बुला रहा है। नुवामा ने टैक्समैको को Buy रेटिंग दी है और 331 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। टैक्समैको के शेयर शुक्रवार को 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ 261.65 रुपये पर बंद हुए थे।

एफडी या डेट फंड, किसमें सुरक्षित रहेंगे आपके पैसे और मिलेगा तगड़ा रिटर्न?

परिवहन विशेष न्यूज

निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को काफी शानदार विकल्प माना जाता है। इसमें आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे साथ ही तय रिटर्न मिलने की गारंटी भी रहती है। इसी तरह डेट फंड में भी कम रिस्क के साथ गारंटीड रिटर्न मिलता है। हालांकि दोनों में निवेश के कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। कोई भी शख्स निवेश करने से पहले अमूमन दो बातों पर गौर करता है। पहला, उसके पैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं और दूसरा, उसे रिटर्न कितना मिलेगा। अगर सुरक्षित निवेश की बात करें, तो आज भी सबसे अधिक भरोसा फिक्स्ड डिपॉजिट पर रहता है। हालांकि, डेट फंड भी कम जोखिम वाले निवेश माने जाते हैं।

आइए जानते हैं कि एफडी और डेट फंड में निवेश के लिए कौन-सा बेहतर है और आपको किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा।

FD में निवेश के फायदे और नुकसान

एफडी की सबसे अच्छी बात है कि आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है और आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग एफडी में निवेश करते हैं। इसमें बड़ी संख्या रिटायर्ड कर्मचारियों की रहती है, जो रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त मिले पैसों की एफडी कर देते हैं।

लेकिन, एफडी के साथ दिक्कत यह है कि इसमें कई दूसरे निवेशों के मुकाबले कम ब्याज मिलता है। ऐसी नौबत आने का खतरा रहता है, जब एफडी का ब्याज मुद्रास्फीति को भी मात नहीं देता। इसका सीधा मतलब आपके मूलधन का नुकसान होता है।

देश में ज्यादातर सरकारी बैंक एफडी पर 6.5 फीसदी दर पर सालाना ब्याज देते हैं। प्राइवेट बैंकों की बात करें, तो यह आंकड़ा 7 फीसदी के आसपास रहता है। वहीं, पिछले पांच साल के दौरान देश में औसत सालाना महंगाई दर पांच फीसदी या इससे अधिक ही रही। इस हिसाब से एफडी का नेट रिटर्न नाममात्र ही नजर आएगा।



यहां मिलता है FD से ज्यादा ब्याज

डेट फंड में कैसा रहेगा निवेश

डेट फंड असल में म्यूचुअल फंड की ही स्कीम होती है। लेकिन, इसमें इक्विटी मार्केट के बजाय कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट जैसे फिक्स्ड इनकम असेट्स शामिल होते हैं, जिससे एफडी की तरह सुरक्षित पूंजी के साथ तय रिटर्न सुनिश्चित किया जाता है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) का डेटा बताता है कि मीडियम ड्यूरेशन वाले टॉप 5 डेट फंड्स के डायरेक्ट प्लान का 5 साल का औसत सालाना रिटर्न काफी अच्छा रहा है। तकरीबन 7.41 फीसदी से लेकर 9.55 फीसदी। कम अवधि वाले डेट फंड ज्यादा सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देने वाले समझे जाते हैं। उनका भी 5 साल का औसत सालाना रिटर्न 7.46 फीसदी से 8.25 फीसदी रहा।

एफडी अच्छा है या डेट फंड?

यह पूरी तरह से आपकी जरूरत और सहूलियत पर निर्भर करता है। हालांकि, कुछ मामलों में एफडी की तुलना में डेट फंड्स बेहतर हैं। डेट फंड्स में लिक्विडिटी अधिक होती है। इसका मतलब कि आप जरूरत पड़ने पर अपनी यूनिट्स बेचकर पैसे निकाल सकते हैं। इसमें एफडी की तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती।

अगर आपका फोकस शत-प्रतिशत पूंजी सुरक्षित रखने पर है, तो आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन, महंगाई दर को मात देने के लिए आप अपनी रकम का कुछ हिस्सा डेट फंड में भी डाल सकते हैं। हालांकि, आप लंबी अवधि वाले डेट फंड्स के मुकाबले कम अवधि वाले फंड्स पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ये अधिक स्थिर होते हैं।

कमी इंटरनेट की दुनिया में रेडिफ का था जलवा, अब बिकने की आई खबर

रेडिफ का इन्फोबीम एक्विजिशन द्वारा अधिग्रहण किया गया, रेडिफ को इन्फोबीम एक्विजिशन ने खरीदा है जिसकी शुरुआत 2007 में विशाल मेहता ने की थी। इन्फोबीम ने देश की सबसे पुरानी इंटरनेट फार्मों में से एक रेडिफ में 54 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। इन्फोबीम ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसने रेडिफ में करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है जो इक्विटी और डेट में बराबर तब्दील होंगे।

नई दिल्ली। भारत की सबसे पुरानी इंटरनेट फर्म है, रेडिफ (Rediff)। इसके साथ लाखों लोगों की यादें जुड़ी हैं। इसकी नींव में अजीत बालकृष्णन (Ajit Balakrishnan) ने रखी थी। रेडिफ ने काफी कम वक्त में अच्छे-खासे यूजर बना लिए। यह न्यूज, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले देश के शुरुआती पोर्टल में एक है। लेकिन, अब रेडिफ के बिकने की खबर आ रही है। गुजरात की फिनटेक कंपनी इन्फोबीम एक्विजिशन ने रेडिफ (Rediff acquired by Infibeam Avenues) में 54 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है।

रेडिफ का शुरुआती सफर
जब 1996 में रेडिफ की शुरुआत हुई, तो उस वक्त देश में गिने-चुने लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेस था। रेडिफ ने अच्छी क्वालिटी की सर्विस देकर जल्द ही यूजर्स के बीच अपनी पहचान बना ली। इसके Rediffmail और Rediff Shopping का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था। उस वक्त रेडिफ शॉपिंग पर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उपकरण बिकते थे।

कायम नहीं रहा दबदबा



रेडिफ.कॉम ने अप्रैल 2001 में इंडिया अग्रॉड अखबार को खरीदा। फिर 2010 में मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए ईमेल सेवा रेडिफमेल एनजी लॉन्च की। इसके दो साल बाद रेडिफ न्यूज के लिए एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च किया। उस वक्त रेडिफ में 300 से ज्यादा लोग काम करते थे। इसके मुख्यालय मुंबई में था और दूसरी शाखाएं बंगलुरु, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क तक में फैली हुई थी।

रेडिफ अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट भी थी। लेकिन, अप्रैल 2016 में कंपनी ने डीलिट होने का फैसला किया। उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। आमदनी के मुकाबले उसकी लागत भी काफी बढ़ गई थी। कुल मिलाकर कंपनी की वित्तीय हालत काफी खस्ताहाल थी।

कैसे बिका रेडिफ

रेडिफ को Infibeam Avenues ने खरीदा है, जिसकी शुरुआत 2007 में विशाल मेहता ने की थी। इन्फोबीम ने देश की सबसे पुरानी इंटरनेट फार्मों में से एक रेडिफ में 54 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। इन्फोबीम ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसने रेडिफ में करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो इक्विटी और डेट में बराबर तब्दील होंगे। इन्फोबीम को इन्वेस्टमेंट के बदले 54 फीसदी शेयरहोल्डिंग मिलेगी। इन्फोबीम का कहना है कि वह सौदे को 90 दिन के भीतर खत्म करना चाहती है।

इन्फोबीम ने क्यों की डील

इन्फोबीम का कहना है कि इस सौदे के जरिए वह पेमेंट, ई-कॉमर्स और क्लाउड

सर्विसेज के लिए एक साझा इकोसिस्टम बनाना चाहती है। उसका इरादा यूजर्स को क्रेडिट, बीमा और निवेश उत्पाद बेचने के लिए रेडिफमनी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना है। रेडिफ को फिलहाल हर महीने लगभग 38 मिलियन ऑनलाइन विजिटर मिलते हैं। रेडिफ ने वित्त वर्ष 2023-24 में 36 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार किया।

इस सौदे से निवेशकों में भी जोश दिखा। शुक्रवार (2 अगस्त) को बीएसई पर 4.87 फीसदी बढ़कर 32.49 रुपये पर बंद हुए, जबकि सेंसेक्स में लगभग 1.1 फीसदी की गिरावट आई थी। इन्फोबीम ने पिछले एक साल में 120 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले 6 महीने के दौरान इसके स्टॉक में 11 फीसदी गिरावट आई है।

75 साल बाद भी अमेरिका से पीछे होगा भारत, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती

पिछले कुछ साल में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि भारत के सामने बड़ी समस्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की रहेगी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत जैसे 100 विकासशील देश मिडिल इनकम ट्रेप में फंस सकते हैं और उनके लिए अमेरिका के बराबर प्रति व्यक्ति आय हासिल करना काफी मुश्किल होगा।

नई दिल्ली। भारत आर्थिक तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना देश के लिए बड़ी समस्या है। विश्व बैंक (World Bank) ने भी अपनी रिपोर्ट में यही चिंता जताई है। उसका कहना है कि भारत समेत 100 से अधिक देश हाई-इनकम वाले देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

World Development Report 2024: The Middle Income Trap रिपोर्ट में प्रतीबिक, भारत को अमेरिका के एक चौथाई प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक पहुंचने में भी करीब 75 साल लगेंगे। इंडोनेशिया भी लगभग 70 साल का समय लेगा। हालांकि, चीन इस



सपनों की उड़ान में चुनौतियां

उपलब्धता को करीब 10 साल में ही हासिल कर सकता है।

मिडिल इनकम ट्रेप बड़ी समस्या
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पिछले 50 वर्षों के सबक का हवाला दिया है। इसमें पाया गया है कि जैसे-जैसे अमीर होते जाते हैं, वे आम तौर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक अमेरिकी जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के 'जाल' में फंस जाते हैं। यह फिलहाल 8,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वर्ल्ड बैंक ने मध्यम आय वाले

देशों के रूप में वर्गीकृत करने की जो सीमा बनाई है, यह उसके मध्य में है।

विकासशील देशों में चुनौतियों का पहाड़
2023 के अंत में 108 देशों को मध्यम आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनमें से प्रत्येक की प्रति व्यक्ति वार्षिक जीडीपी 1,136 अमेरिकी डॉलर से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच थी। ये देश छह अरब लोगों का घर हैं, मतलब कि दुनिया की 75 फीसदी इन्हीं 6 देशों में

गुजर-बसर करती है। यहां हर तीन में से दो लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। आगे की राह देखें, तो अतीत के मुकाबले चुनौतियां और भी ज्यादा कड़ी हैं। इन देशों में आबादी और कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। भू-राजनीतिक और व्यापार से जुड़ी दिक्कतों में भी झंजाफा हो रहा है। इनके सामने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने की चुनौती भी है।

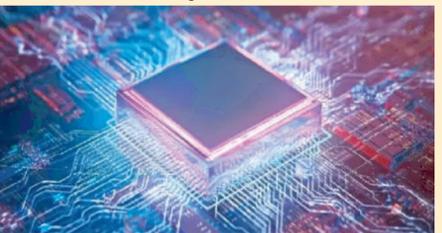
इंटेल के शेयरों में तबाही: 26 फीसदी गिरे चिपमेकर कंपनी के स्टॉक, निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा

अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को इंटेल के स्टॉक 26 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। यह पिछले पांच दशक में इंटेल के शेयरों का सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में इंटेल के स्टॉक ने एक दिन में 31 फीसदी का गोता लगाया था। उस वक्त कंपनी को लिस्ट हुए सिर्फ 3 ही साल हुए थे। इंटेल के तीसरी तिमाही के नतीजे हद से ज्यादा खराब रहे थे।

नई दिल्ली। अमेरिकी चिपनिर्माता इंटेल (Intel) ने कई सालों तक मार्केट में एकछत्र राज किया। लेकिन, अब कंपनी शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। कंपनी एआई प्रोसेसर के मामले में भी कोई बड़ी तरक्की नहीं कर पा रही। उसका दूसरी तिमाही के नतीजे भी बेहद निराशाजनक रहे।

इंटेल के शेयरों का बुरा हाल
इन सबका असर इंटेल के शेयरों पर भी दिखा। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में इंटेल के स्टॉक 26 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। यह पिछले पांच दशक में इंटेल के शेयरों का सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में इंटेल के स्टॉक ने एक दिन में 31 फीसदी का गोता लगाया था। उस वक्त कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए सिर्फ 3 ही साल हुए थे।

10 के निचले स्तर पर इंटेल
शुक्रवार को इंटेल के स्टॉक (Intel Share Price) 26.06



फीसदी टूटकर 21.48 डॉलर (1,79,999 रुपये) पर आ गई। यह पिछले एक दशक में कंपनी के शेयरों का सबसे निचला स्तर है। टूट गई और इसके शेयर 10 साल (2013 के बाद) के निचले स्तर पर पहुंच गए। इंटेल के शेयरों ने पिछले 6 महीने में करीब 50 फीसदी और पांच साल में 55 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।

छटनी करने का भी एलान
इंटेल को तीसरी तिमाही में 1.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। कंपनी ने घाटा और कामकाजी खर्च करने के लिए करीब 18 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। उसने चौथी तिमाही के लिए निवेशकों को दिए जाने वाले डिविडेंड को भी निरस्त कर दिया। कंपनी अपने खर्चों में कुल 20 अरब डॉलर की कमी लाने की योजना बना रही है।

'छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत', पीएम मोदी बोले- कई देशों में काम आ सकता है हमारा मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है। भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिन्हें दुनिया सुपरफूड कहती है और उसे हमने श्रीअन्न की पहचान दी। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषण को भी जरूरी बताया। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। यहां के 90 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम जमीन है। कई विकासशील देशों की भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए हमारा मॉडल कई देशों के काम आ सकता है।

पांच दिन चलेगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों का यह 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जो पांच दिनों तक चलेगा। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कृषि हमारी आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे।

दूध, दाल व मसालों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक

भारत में पहला कृषि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1958 में हुआ था। पीएम मोदी ने 65 वर्ष पहले के उस दौर को याद करते हुए कहा कि तब भारत आजाद ही हुआ था और हमारी खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती थी, मगर आज हम खाद्य अधिशेष देश हैं। दूध, दाल एवं मसालों का सबसे बड़ा तथा खाद्यान्न, फल सब्जी, कपास, चीनी, चाय एवं मछली का दूसरा बड़ा उत्पादक हैं।

बजट में कृषि के सतत विकास पर फोकस
खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा के लिए भी हम दुनिया को समाधान दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को प्रोन्नत कर रहे हैं। इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। इस साल के बजट में कृषि के सतत विकास पर बड़ा फोकस है। हमारा जोर शोध पर है। दस सालों में हमने जलवायु के अनुकूल फसलों की 19 सौ



प्रजातियां दी हैं।

सुपरफूड के रूप में उभरा काला चावल
पीएम ने कहा कि चावल की कुछ किस्में ऐसी हैं, जिन्हें 20 प्रतिशत तक पानी चाहिए। काला चावल सुपरफूड के रूप में उभरा है। हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ हो रहा है। कृषि की चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के साथ ही पोषण बड़ी चुनौती है। इसका समाधान भारत के पास है।

देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र
पीएम ने कहा कि हम मिलेट्स के सबसे बड़े

उत्पादक हैं। अपने इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का मजबूत इकोसिस्टम है। इंडियन कार्डसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च के ही सौ से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। कृषि और संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए पांच सौ से ज्यादा कॉलेज हैं। सात सौ से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं।

प्राचीन कृषि परंपरा का जिक्र भी किया
पीएम ने अर्थशास्त्रियों को भारत की प्राचीन कृषि परंपरा के बारे में भी बताया। कहा कि भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही पुरानी कृषि को लेकर हमारी

मान्यताएं हैं। खाद्यान्न और पोषण पर आज इतनी चर्चा हो रही है, किंतु हजारों वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। इसीलिए अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है, जो भारतीय जीवन का हिस्सा है।

ग्रंथ का किया जिक्र
पीएम ने कहा कि दो हजार वर्ष पहले का ग्रंथ कृषि पराशर वैज्ञानिक खेती का दस्तावेज है। इसमें कृषि पर ग्रहों एवं नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, वर्षा को नापने का तरीका, मौसम पूर्वानुमान, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा, भंडारण आदि अनेक विषयों पर विस्तार से बताया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर एक ट्रक के कुचलने से 2 कावडिया सहित 3 लोगों की मौत हो गई है



मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उडीशा, भुवनेश्वर : गजाम जिले के खल्लोकोट में डिमिरिया विलेज स्ट्रीट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर एक ट्रक के कुचलने से 2 कावडिया सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक कौडिया का नाम रंजी नायक है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पायी है। वे बानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अन्य मृतक ए. बनमाली पात्र है। एनजी नायक और उनके अन्य कौडिया साथी रुशिकुल्या नदी से पानी लेकर बानपुर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गये। उनकी मौत पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर खल्लोकोट अस्पताल में बनमाली पात्र को मृत घोषित कर दिया गया। ट्रक के ऊपर तीन लोगों के सवार होने से ट्रक पलट गया। हालांकि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। खल्लोकोट पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया और ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक आंध्र प्रदेश से भुवनेश्वर जा रहा था।

पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जयदेव जेना ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया

भुवनेश्वर : पीसीसी कमेटी भंग होने के बाद ओडिशा कांग्रेस निष्क्रिय हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जयदेव जेना ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी में अफरा-तफरी मची हुई है। जयदेव ने पत्र में अनुरोध किया है कि जो व्यक्ति पार्टी को आगे ले जाएगा उसे तुरंत पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। उन्होंने पत्र में कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने का भी प्रस्ताव दिया। उधर, कांग्रेस विधायकों के नेता रामचन्द्र कदमत ने कहा, पीसीसी अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देगे जो आलाकमान के लिए योग्य हो। कदमत ने कहा कि हाइकमान इस बात पर विचार कर रहा है कि जो भी टीम को संगठित कर सके उसे जिम्मेदारी दी जाए।



डॉ. लॉजिस्टिक्स: भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चैन पर जागरूकता बढ़ाएं

डॉ. अंकुर शरण

वर्तमान समय में लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चैन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। युवा शक्ति को इस क्षेत्र में तैयार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। भारत सरकार कई प्रमुख पहल कर रही है जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास। ये पहलें लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद कर रही हैं।

दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स को डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ग्रीन लॉजिस्टिक्स जैसी नई तकनीकों से उन्नत किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि यह किसी भी उद्योग की रीढ़ है। इन अवसरों और सरकारी प्रयासों के साथ, युवा पेशेवरों के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चैन में करियर बनाने के कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे वे न केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में करियर के अवसर

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में करियर के अवसर आज के युवा aspirants के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें कई प्रकार की नौकरियों और करियर के विकल्प मौजूद हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं जो युवा aspirants को प्रेरित करेंगे:

विविधता और विकास:

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जो उद्योगों की विविधता को संभालता है। चाहे वह निर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, या ई-कॉमर्स हो, सभी को लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र निरंतर विकासशील है और इसमें नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के कारण हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं।

रोजगार के अवसर:

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में कई प्रकार की नौकरियों के अवसर हैं, जैसे कि वेयरहाउस मैनेजर, सप्लाइ चैन एनालिस्ट, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, और इन्वेंट्री प्लानर। हर नौकरी का अपना महत्व है और ये सभी मिलकर सप्लाइ चैन को सुचारू रूप से चलाते हैं।

कौशल विकास:

इस क्षेत्र में काम करने से विभिन्न कौशलों का विकास होता है, जैसे कि समस्या समाधान, संचार कौशल, डेटा एनालिसिस, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कौशल न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सहायक होते हैं।

उन्नति के अवसर:

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में उन्नति के कई अवसर होते हैं। एक इंटी-लेवल पोजीशन से शुरू होकर आप मैनेजमेंट और सीनियर लेवल पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। सही अनुभव और शिक्षा के साथ, इस क्षेत्र में उन्नति की संभावना बहुत अधिक है।

सामाजिक योगदान:

लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट का सामाजिक योगदान भी महत्वपूर्ण है। यह



सुनिश्चित करता है कि उत्पाद और सेवाएँ समय पर उपभोक्ताओं तक पहुँचें, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस क्षेत्र में काम करने से आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

युवा aspirants के लिए लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट एक रोमांचक और संतोषजनक करियर विकल्प हो सकता है। इसमें न केवल विविधता और विकास के अवसर हैं, बल्कि यह समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान देने का मौका देता है। इस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं!

प्रश्न 1: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में करियर कैसे शुरू करें?

उत्तर: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में करियर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप बीबीए, एमबीए, या लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में विशेष पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा, इंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको व्यावहारिक अनुभव देता है, बल्कि नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करता है।

प्रश्न 2: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में किन-किन क्षेत्रों में नौकरियाँ उपलब्ध हैं?

उत्तर: इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जैसे:

- वेयरहाउस मैनेजर
- सप्लाइ चैन एनालिस्ट
- लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर
- ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर
- इन्वेंट्री प्लानर
- प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट
- शिपिंग और रसीद अधिकारी
- कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव

प्रश्न 3: इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए

किन कौशलों की आवश्यकता होती है?

उत्तर: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित कौशलों की आवश्यकता होती है:

- समस्या समाधान कौशल
- प्रभावी संचार कौशल
- डेटा विश्लेषण कौशल
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
- समय प्रबंधन
- तकनीकी ज्ञान और सॉफ्टवेयर की समझ
- टीमवर्क और नेतृत्व कौशल

प्रश्न 4: इस उद्योग में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: इस उद्योग में निम्नलिखित मुख्य चुनौतियाँ हो सकती हैं:

- बदलती उपभोक्ता मांग और उनकी अपेक्षाएँ
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, या राजनीतिक अस्थिरता
- लागत प्रबंधन और लाभप्रदता बनाए रखना
- तकनीकी उन्नति और इसके साथ तालमेल बताना

प्रश्न 5: पर्यावरणीय मुद्दों और स्थिरता पर ध्यान देना

उत्तर: इस उद्योग में उन्नति के कई अवसर हैं। आप इंटी-लेवल पोजीशन से शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे मैनेजमेंट और सीनियर लेवल पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। उन्नति के लिए अनुभव, शिक्षा और अतिरिक्त प्रमाणपत्रों का होना आवश्यक है। इसके अलावा, नेतृत्व कौशल और नवाचार के प्रति जागरूकता भी महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 6: इस क्षेत्र में कार्य करने के लाभ क्या हैं?

उत्तर: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में कार्य करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

विविध करियर विकल्प और भूमिकाएँ

उच्च वेतन और लाभकारी पैकेज

उन्नति और विकास के अवसर
नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के साथ काम करने का मौका

सामाजिक योगदान और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना

प्रश्न 7: इस क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियाँ और उन्नतियाँ क्या हैं?

उत्तर: लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में नवीनतम प्रवृत्तियाँ और उन्नतियाँ निम्नलिखित हैं:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एकीकरण ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग स्वचालित वेयरहाउस और रोबोटिक्स ई-कॉमर्स और ओमीचैनल सप्लाइ चैन का विकास

पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रीन लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट में करियर बनाने के ये महत्वपूर्ण बिंदु और चुनौतियाँ युवा aspirants को प्रेरित करेंगी और उन्हें इस क्षेत्र में सफल होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

भारत सरकार लॉजिस्टिक उद्योग के लिए क्या कर रही है

भारत सरकार लॉजिस्टिक उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलें दी जा रही हैं:

1. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy)

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह नीति कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, और स्किल डेवलपमेंट।

2. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multimodal Logistics Parks)

भारत सरकार ने देशभर में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ये पार्क विभिन्न परिवहन मोड्स (जैसे सड़क, रेल, और जलमार्ग) को जोड़कर लॉजिस्टिक्स की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। यह पहल लॉजिस्टिक नेटवर्क को अधिक समग्र और कुशल बनाती है।

3. प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना (PM GatiShakti)

प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास करना है। इस योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है ताकि सड़क, रेल, वायु, और जलमार्गों को एकीकृत किया जा सके और लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके।

4. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridors)

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य माल परिवहन के लिए विशेष रूप से समर्पित रेल कॉरिडोर स्थापित करना है। यह परियोजना माल ढुलाई की गति और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

5. सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project)

सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत के समुद्री परिवहन नेटवर्क को सुधारना और बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। इसके तहत बंदरगाहों के पास लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं और जलमार्गों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

6. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project)

भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देशभर में सड़क नेटवर्क को सुधारना और नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाना है। इससे लॉजिस्टिक परिवहन की गति और दक्षता बढ़ेगी।

7. डिजिटल लॉजिस्टिक्स

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉजिस्टिक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। ई-वे बिल सिस्टम, जीएसटी पोर्टल, और अन्य डिजिटल टूल्स का उपयोग लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बना रहा है।

8. लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index)

सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) लॉन्च किया है। यह सूचकांक राज्यों को अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

9. कौशल विकास और प्रशिक्षण (Skill Development and Training)

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कई प्रशिक्षण संस्थानों और आईटीआई के माध्यम से लॉजिस्टिक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया है।

भारत सरकार की ये पहलें लॉजिस्टिक उद्योग को अधिक प्रभावी, समन्वित और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगी बल्कि उद्योग के समग्र विकास और रोजगार सृजन में भी सहायक सिद्ध होंगी।

डॉ. लॉजिस्टिक्स

डॉ. लॉजिस्टिक्स एक पहल है जो आज की दुनिया में लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चैन मैनेजमेंट का अवलोकन साझा करती है। यह पहल आपको इस क्षेत्र की गहन समझ और आत्मविश्वास प्रदान करती है ताकि आप इसे अपने करियर के रूप में चुन सकें। डॉ. लॉजिस्टिक्स के माध्यम से, आपको काम करने के कई अवसर मिलते हैं और आप इस उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो सकते हैं।

ankur.supplychain@gmail.com